

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 04 सितम्बर, 2006

में विचारणीय विषयों की



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक

04 सितम्बर, 2006 में विचारणीय विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	08
3.	बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में। (बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्या: 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या)	22
4.	ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	26
5.	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्तन।	27
6.	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मजिले ब्लॉक्स का निर्माण कार्य।	31
7.	एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।	34
8.	हाइटिक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी. पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	53

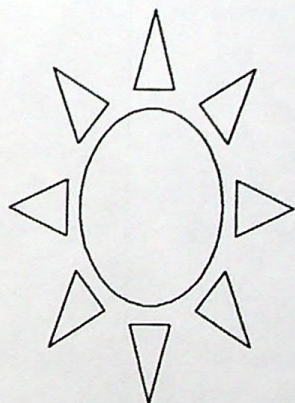
9.	मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस-281 तथा एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	54
10.	खसरा संख्या: 221 स, निकट टी.वी.टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	56
11.	श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	57
12.	प्रदेश की प्रथम भू-जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	62
13.	ह्युमन ऐण्ड एजुकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में।	64
14.	प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर- बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्तित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	67
15.	कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी-1 में एसएस-111 के ग्रीनबेल्ट में आवन्तित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या।	89
16.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 02 मई
2006 के कार्यवृत्त
की पुष्टि।



पुष्टिकरण



लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक
02 मई, 2006 का
कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न
है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006
में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | श्री राकेश कुमार मित्तल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री के.एल.मीना | सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन। |
| 3. | श्री बी०बी०सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 4. | श्री राम गणेश | जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ। |
| 5. | श्री वी.पी.सिंह | नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम। |
| 6. | श्री ओम नारायण, | निदेशक, कोषागार। |
| 7. | श्री एन.आर.वर्मा | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 8. | श्री पी.के.जैन | मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, |
| 09. | श्री सी.एन.हार्डी | मुख्य वास्तुविद, उ०प्र०आवास
एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 10. | श्री एल.एस.पी.सिंह | पर्यटक अधिकारी, पर्यटन विभाग। |
| 11. | डा. फिदा हुसैन अंसारी | सदस्य, ल.वि.प्रा.। |

अन्य उपस्थिति:

- | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| 12. | श्री राम बिलास यादव | सचिव, ल.वि.प्रा., लखनऊ। |
| 13. | श्री एस.डी. दोहरे | अपर सचिव, ल.वि.प्रा.। |
| 14. | श्री सी०पी०शर्मा | मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०। |
| 15. | डा. मोहन यादव | वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.। |
| 16. | श्री दवनराम यादव | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०। |

नवागन्तुक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री राम बिलास यादव के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के प्रस्ताव संख्या : 15 एवं 30 पर गठित उपसमिति की आख्या अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 एवं 28 के सम्बन्ध में उपसमिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

✓

- विषय संख्या : 3 कानपुर रोड योजना भाग-1,2,3 व 4 में बेल्टिंग/गडढे हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग-3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।
- निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
- विषय संख्या : 4 वर्ष 2005-06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-07 का मूल आय-व्ययक।
- निर्णय : वित्तीय वर्ष 2005-06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-07 का मूल आय-व्ययक सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक द्वारा आय-व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से वर्ष 2005-06 के वास्तविक तथा 2006-07 का मूल आय-व्ययक अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 5 जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकनोपरान्त संज्ञान में लिया गया।
- विषय संख्या : 6 डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी एवं प्रस्ताव अविलम्ब शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9/

- विषय संख्या : 7 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- विषय संख्या : 8 गोमती नगर विस्तार योजना भाग-2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
- विषय संख्या : 9 सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।
- निर्णय : भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 10 कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्लिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

9/

विषय संख्या : 11 कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर डी-1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज-III में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्तित भूखण्डों के कारण स्थल का भू-प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

1. सचिव, ल.वि.प्रा.,
2. मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.,
3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जायेगा कि ग्रीन बेल्ट में भूखण्डों के सृजन एवं आवन्तन हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं।

विषय संख्या : 12 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त भू-उपयोग सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र एवं शेष भाग पर कनवीनियेन्ट शाप्स बनाई जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दोनों के प्रवेश द्वार अलग-अलग रहें।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भौति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

07

विषय संख्या : 14 बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवन्तित प्ले-फील्ड की भूमि का भू-उपयोग प्ले-फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिन्टन एकादमी के मानकों के आधार पर निर्माण अनुमन्य करते हुए, बड़े हुए भू-भाग की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनिंग प्राविधानों में निर्धारित मानक से अधिक भू-आच्छादन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर शासन स्तर से भू-आच्छादन निर्धारित मानक से अधिक किया जाना सम्भव न हो तो प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग प्लेफील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्या : 16 ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 15 " सरल शमन योजना-2002 के अन्तर्गत श्री वृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्या : 34 ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तन के सम्बन्ध में" गठित उपसमिति की आख्या।

निर्णय : उपसमिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

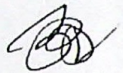
07

विषय संख्या : 17 ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय
संख्या : 30 " भूखण्ड संख्या : 13, राणा प्रताप मार्ग पर
निर्मित ब्लाक-ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ
महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के कम में अनुमति
दिये जाने के सम्बन्ध में " गठित उपसमिति की आख्या।

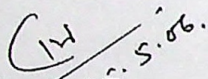
निर्णय : प्रस्तुत की गई उपसमिति की आख्या पर विचारोपरान्त
जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने
से सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक
समाप्त हुई।

3
(डा.राम बिलास यादव)
सचिव


(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(आर.के.मिस्तल)

आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या : 2

पृष्ठ संख्या : 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय क्रमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के प्रस्ताव संख्या : 15 एवं 30 पर गठित उपसमिति की आख्या अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 एवं 28 के सम्बन्ध में उपसमिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।	ल.वि.प्रा. की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 28 पर गठित उपसमिति की आख्या विषय संख्या: 3 के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 पर गठित समिति की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है क्योंकि पक्ष से अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र उपलब्ध कराने का लिखा गया है किन्तु

			अभी तक मानचित्र प्राप्त न होने के फलस्वरूप कार्यवाही लम्बित है।
3	कानपुर रोड योजना भाग-1,2,3 व 4 में बेल्टिंग/गड्ढे हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग-3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।	परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।
4	वर्ष 2005-06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-07 का मूल आय-व्ययक।	वित्तीय वर्ष 2005-06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-07 का मूल आय-व्ययक सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक द्वारा आय-व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से वर्ष 2005-06 के वास्तविक	बोर्ड द्वारा अनुमोदित आय-व्ययक 2006-07 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

		तथा 2006-07 का मूल आय-व्ययक अनुमोदित किया गया।	
5	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव।	प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकनोपरान्त संज्ञान में लिया गया।	शासन द्वारा निर्माण कार्य का दायित्व राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया है। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
6	डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी एवं प्रस्ताव अविलम्ब शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णयानुसार भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को दिनांक 06.06.2006 को प्रेषित किया जा चुका है।
7	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।	प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
8	गोमती नगर विस्तार योजना भाग-2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

9	सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।	भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।
10	कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्लिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।	बोर्ड द्वारा गठित उपसमिति द्वारा दिनांक 6.7.2006 को स्थल निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल लखनऊ महायोजना 2021 में एस.टी.पी. के लिये आरक्षित एवं उपयुक्त पाया गया। पृष्ठ- 15 से 21 तक समिति की संस्तुति अवलोकनार्थ संलग्न है।
11	कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर डी-1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज-III में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्तित भूखण्डों के कारण स्थल का	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई : 1. सचिव, ल.वि.प्रा., 2. मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा., 3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	निर्णयानुसार समिति द्वारा बैठक की गई। समिति की संस्तुति पृष्ठ-89 पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

	कारण स्थल का भू-प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण। उपरोक्त समिति द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जायेगा कि ग्रीन बेल्ट में भूखण्डों के सृजन एवं आवन्तन हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं।	
12	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त भू-उपयोग सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र एवं शेष भाग पर कनवीनियेन्ट शाप्स बनाई जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दोनों के प्रवेश द्वार अलग-अलग रहें।	लिये गये निर्णय के क्रम में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
13	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भौति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।	निरस्त किया गया।
14	बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिन्टन	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सचिव,

	आवन्तित प्ले-फील्ड की भूमि का भू-उपयोग प्ले-फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	एकाडमी के मानको के आधार पर निर्माण अनुमन्य करते हुए, बड़े हुए भू-भाग की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनिंग प्राविधानों में निर्धारित मानक से अधिक भू-आच्छादन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर शासन स्तर से भू-आच्छादन निर्धारित मानक से अधिक किया जाना सम्भव न हो तो प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग प्लेफील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।	बैडमिन्टन एकेडमी को भू-आच्छादन के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 26.6. 2006 द्वारा अवगत करा दिया गया है, किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
15	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।
16	ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 15 " सरल शमन योजना-2002 के अन्तर्गत श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्या : 34 ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के	उपसमिति द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।	निरस्त किया गया।

	आवासीय भू-उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तन के सम्बन्ध में" गठित उपसमिति की आख्या।		
17	ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 30 " भूखण्ड संख्या : 13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लॉक-ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के क्रम में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में " गठित उपसमिति की आख्या।	प्रस्तुत की गई उपसमिति की आख्या पर विचारोपरान्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया गया।	निरस्त किया गया।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्थाओं, शोधन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में उ०प्र० जल निगम, जल संस्थान लखनऊ तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की सम्पन्न हुयी

बैठक दिनांक 04.07.2006 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्नानुसार।

मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आहुत की गई बैठक में, बैठक के उद्देश्यों, आवश्यकता पर विस्तृत रूप से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया कि,

- लखनऊ महानगर की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्थाओं का विरचन एवं सम्पादन तैयार की गयी महायोजनाओं के अनुरूप ही किये जाने पर कार्यवाही की जाये।
- विभिन्न विभागों द्वारा परियोजनाओं के विरचन एवं सम्पादन, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं उन्हें नगर की भविष्य की योजनाओं के अनुरूप विकसित करने, सही तकनीकी का समावेश करके पर्याप्त अनुरक्षण व संचालन की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों द्वारा सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- विकसित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं में कमी अवरोध यदि कोई है के सुधार एवं निस्तारण तक आवश्यकतानुसार सुदृढिकृत करने तथा विकासशील योजनाओं में सीवरेज, ड्रेनेज के कार्य, भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत करने का प्रयास किया जाये।
- शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति भूमिगत जल के अनियंत्रित दोहन से भूमिगत स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिंता व्यक्त की गयी। भूतल पेयजल के उपयोग की योजना तैयार करने और आवश्यकतानुसार कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिये।
- लखनऊ के लिये भूतल-जल के सुविधाजनक स्रोत गोमती नदी को शहरी विकास से उत्पन्न होते प्रदूषण से बचाव के हर सम्भव प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। गोमती प्रदूषण नियन्त्रण की योजनाएँ उ०प्र० जल निगम द्वारा स्वीकृत करायी गयी है किन्तु उनकी जानकारी अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ०प्र० आवास विकास परिषद, प्राईवेट डेवलपर्स को नहीं है। जल निगम द्वारा इसका प्रचार-प्रसार करते हुये कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के प्रस्तावित कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव सूचित किये जाने की आवश्यकता है।
- यह भी अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में लखनऊ महायोजना 2001 के अन्तर्गत सीवरेज, ड्रेनेज, राईजिंग मेन तथा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के प्रस्ताव किये गये थे। संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 के प्रस्तावों में योजना के पूर्व में प्रेषित तकनीकी प्रस्ताव प्रभावित होंगे और लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकताओं की पूर्ति कदाचित् सम्भव नहीं होगी। अतः वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप परियोजना में तकनीकी समावेश, संशोधन एवं पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

[Signature]

गोमती नगर एवं संबंधित क्षेत्र, 2. कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 3. सीतापुर रोड योजना, अलीगंज योजना, जानकीपुरम् योजना एवं संबंधित क्षेत्र, 4. वसंत कुंज योजना, हरदोई रोड योजना एवं संबंधित क्षेत्र की सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजनाओं पर जिस ओर लखनऊ का विकास तीव्रता से हुआ है/प्रस्तावित है/सम्भावित है की सीवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करते हुये नियंत्रित सुनियोजित एवं दीर्घकालिक परियोजनाओं का विरचन किये जाने एवं तदनुसार विकास/निर्माण की आवश्यकता है।

इन परियोजनाओं में स्वीकृत परियोजना के मूल्य में वर्तमान आवश्यकता को सम्मिलित करते हुये लागत में यदि वृद्धि हो रही है तो इस क्षेत्र के विकासकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं/आवंटियों से अवस्थापना सुविधा के लिये धनराशि वसूल की गयी है। अतः विकसित होने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त अन्तर की धनराशि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा किये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

बैठक के उद्देश्यों की विवेचना के उपरान्त, महाप्रबन्धक गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई श्री बी०यू० बिश्नाई द्वारा गोमती एक्शन प्लान में स्वीकृत परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रस्ताव से उपस्थित अभियन्ताओं को अवगत कराया गया।

जी.एम., जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान दो चरणों में पूर्ण कराया जाना है। प्रथम चरण में दौलतगंज में 42 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना कर दी गयी है और कार्यरूप में है।

द्वितीय चरण में गोमती में गिरने वाले 20 नालों जिसमें सिस गोमती क्षेत्र के 8 व ट्रांस गोमती क्षेत्र के 12 नालों को टेप करना तथा ककरहा में 370 एम०एल०डी० का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्माण करने, पम्पिंग स्टेशन व राईजिंग मेन डालने के कार्य हेतु गोमती प्रदूषण नियन्त्रण में 263.00 करोड़ की योजना स्वीकृत है एवं इसके अधीन स्वीकृत कार्य कराये जा रहे हैं।

स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष ग्वारी कल्वर्ट के पास मुख्य पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रगति पर है। जिसमें टेप किये गये नाले व गोमती नगर योजना फेज-1 एवं 11 की सीवरेज व्यवस्था को टेप करते हुये ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट तक शुद्धीकरण हेतु भेजने व शुद्धीकरण करने के कार्य प्रस्तावित हैं।

यह भी अवगत कराया गया कि Japan International Corporation Agency (जायका) के प्रयास से लखनऊ महानगर की सीवर व्यवस्था एवं इसके ट्रीटमेंट के लिये फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं इसके आधार पर सीवरेज महायोजना के अवशेष कार्यों को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में ₹0 2525.00 करोड़ की योजना 30प्र० जल निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

लखनऊ महायोजना 2021 की आवश्यकता के अनुरूप सीवरेज महायोजना में कुल 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट क्रमशः ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये ककरहा में 375 एम.एल.डी., सिस गोमती डिस्ट्रिक्ट-1 में दौलतगंज-42 एम.एल.डी., डिस्ट्रिक्ट-2 ख्वाजापुर में 152 एम.एल.डी. डिस्ट्रिक्ट-4 मल्लेसुमरु में 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट प्रस्तावित किये गये हैं और सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये सीवर लाईन, पम्पिंग स्टेशन, राईजिंग मेन के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं।

दौलतगंज में निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 42 एम.एल.डी. से बढ़ाकर 56 एम.एल.डी. करने की आवश्यकता प्राधिकरण की विकसित की जा रही कालोनी बसन्त कुंज के दृष्टिगत आवश्यक है। क्षमता वृद्धि की योजना बनाई जा रही है।

ककरहा में प्रस्तावित एवं स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिये भूमि की व्यवस्था तत्काल आवश्यक है जहाँ पर स्वीकृत योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रस्तावित किया गया था, संशोधित लखनऊ महायोजना 2021 में उस क्षेत्र को आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित कर दिया गया है। अतः लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही तुरन्त कराई जानी आपेक्षित

स्थल परिवर्तन के कारण परियोजना में लगभग ₹0 300 लाख की वृद्धि सम्भावित है। स्थल परिवर्तन प्राधिकरण की भावी योजनाओं के हित में है तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं उपयोग प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर फेज 1, फेज 2 एवं गोमती नगर विस्तार की आवश्यकताओं के लिये भी किया जाना है। अतः परियोजना के मूल्य में संभावित वृद्धि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा किये जाने पर विचार किया जाना है जिसके लिये विकास प्राधिकरण में आवंटियों से धन प्राप्त करने की कार्यवाही आपेक्षित है।

ख्वाजापुर में प्रस्तावित 152 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका निर्माण जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में प्रस्तावित किया गया है का भी स्थल परिवर्तन लखनऊ महायोजना 2021 के अनुरूप आवश्यक है और यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना, मानसरोवर योजना, शारदानगर योजना के लिये मूल रूप से निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। अतः योजना के लिये प्रस्तावित लागत ₹0 493.31 करोड़ की 70 प्रतिशत धनराशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन से वित्त पोषित होगी। शेष धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किये जाने पर विचार किया जाना है क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिये ही आवश्यक है और इस सेवा के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों से धनराशि प्राप्त की कार्यवाही आपेक्षित है।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में 30प्र0 जल निगम एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ दिनांक 06.07.2006 को स्थल निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल लखनऊ महायोजना 2021 में एस.टी.पी. के लिये आरक्षित और उपयुक्त पाया गया। भूमि अर्जन की कार्यवाही तत्काल किया जाना आपेक्षित है। निरीक्षण के समय कानपुर रोड योजना की वर्तमान वर्षा जल निकासी व्यवस्था की स्थिति भी देखी गयी, किला मोहम्मदी ड्रेन से वर्तमान जल निकासी व्यवस्था की इटूरिया पुलिया के सेक्शन को उपयुक्त नहीं पाया गया, साथ ही लगभग 50 किमी० लम्बे किला मोहम्मदी ड्रेन को अनुरक्षण एवं उपयुक्त बनाये रखने पर फिजिबिलिटी का अध्ययन कराने की कार्यवाही आपेक्षित है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 1994-95 में प्राधिकरण की योजनाओं क्रमशः शारदानगर, कानपुर रोड एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वर्षा जल निकासी हेतु योजनाएँ नीलमत्था ड्रेन रेलवे लाइन के साथ सिंचाई विभाग की कालोनी के मध्य से शारदानगर स्केप के एलाइन्मेंट में ड्रेन के निर्माण जिसमें लगभग 4 किमी० में 8 मी० का लेविल डिफरेंस था, का अध्ययन कराया गया था। आई०आई०टी० के प्रोफेसर को स्थल निरीक्षण कराया गया तथा परियोजना तैयार कराई गई थी। शारदा नहर पर

एक्वाडक्ट की डिजाइन का प्रस्ताव भी सिंचाई विभाग को भेजा गया था एवं तैयार कराया गया था। किन्तु परिस्थितियों में इस योजना को स्थगित किया गया था, जानकारी नहीं हो पाई है।

मस्तेमऊ में प्रस्तावित 328 एम.एल.डी. के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं अन्य कार्य हेतु डिस्ट्रिक्ट जॉन-4 के लिये 30प्र0 जल निगम द्वारा 971.06 करोड़ की परियोजना है इस क्षेत्र में आवास विकास परिषद की वृन्दावन योजना तथा हाईटेक टाउनशिप का क्षेत्र प्रस्तावित है। अतः वित्तपोषण हेतु संबंधित निर्माण/विकास करने वाली संस्थाओं से विचार कर 30 प्रतिशत वित्त पोषण पर भी निर्णय लिये जाने की कार्यवाही आपेक्षित है।

दौलत गंज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संशोधित उत्प्रवाह का उपयोग सिंचाई कार्यों में करने पर चर्चा की गयी। लखनऊ महानगर में हजरतगंज से सीतापुर रोड छोटा इमामवाड़ा तक दोनों तरफ बहुत बड़े भू-भाग पर सरोजनी नायडू पार्क, लक्ष्मण पार्क, बेगम हजरत महल पार्क, शहीद पार्क, सूरज कुण्ड पार्क, महावीर पार्क, बुद्धा पार्क, नीचू पार्क, गुलाब वाटिका, घण्टाघार पार्क आदि ऐसे पार्क हैं जिनकी सिंचाई व्यवस्था भूमिगत जल से की जा रही है और भूतल जल स्रोतों में दिन प्रतिदिन हो रही कमी के दृष्टिगत यह उचित नहीं है। भूमिगत जल का पेयजल में उपयोग किया जाना ही उचित है। भूमिगत जल का संरक्षण प्रथम वरीयता पर विचारणीय है। अतः ऐसी परियोजना तैयार करने का निर्देश विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता, जॉन-8 को दिये गये कि जल संस्थान व जल निगम के क्षेत्रीय अभियन्ताओं के सहयोग से ट्रीटेड सीवेज का उपयोग कर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गयी। यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि यह परीक्षण करा लें की दौलतगंज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शुद्धीकृत जल का उपयोग औद्यानिक कार्यों में करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

महाप्रबन्धक (गोमती), जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्वारी कल्वर्ट पर निर्माणाधीन एम.पी.एस. जो कि गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, में गोमती नगर क्षेत्र के सीवेज के कलैक्शन की व्यवस्था भी की जानी सम्भव है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस व्यवस्था हेतु पूर्व में प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹0 984.52 लाख बनाया गया था, परन्तु अब जल निगम द्वारा इस हेतु ₹0 299.49 लाख का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया जिसमें इस कार्य में लगभग ₹0 685.03 लाख प्राधिकरण को वचत होगी। इस धनराशि की मांग जल निगम द्वारा पत्र सं0 1190/W-27/22 दिनांक 02.05.2006 के माध्यम से की गयी है, जिसको कि तुरन्त से जल निगम को दिया जाना आपेक्षित ताकि यह कार्य समयान्तर्गत पूर्ण हो सके।

गोमती नगर विस्तार फेज-1,2,3 के लिये सीवेज व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी, महाप्रबन्धक, जल निगम से अनुबंध किया गया कि प्राधिकरण की इस योजना के लिये पम्पिंग स्टेशन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक राईजिंग मेन की योजना तैयार कराई जाये ताकि प्राथमिकता पर कार्य कराया जा सके। महाप्रबन्धक द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना फेज-1,2,3 की तकनीकी सूचनाएँ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, इस हेतु अधिशासी अभियन्ता जॉन-1 से अपेक्षा की गयी की समस्त सूचनाएँ कन्सल्टेंट से विचार विमर्श कर जल निगम को उपलब्ध करा दें।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया, कि कानपुर रोड एवं मोहान रोड के मध्य लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के

लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु महायोजना में भूमि आरक्षित है। अतएव इस क्षेत्र की सीवेज व्यवस्था हेतु सीवेज महायोजना में तदनुसार प्रस्ताव सम्मिलित किए जाएं।

ड्रेनेज:-

नगरीय क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था एवं विकसित होने वाले क्षेत्रों की ड्रेनेज व्यवस्था एवं गोमती में गिरने वाले गन्दे नालों को टेप कर शुद्धीकृत करने पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्धक, गोमती एक्शन प्लान श्री बिश्नोई द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती एक्शन प्लान में गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप कर ककरहा में शुद्धीकृत करने की परियोजना स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है। वर्तमान योजना में हैदर कैनल को भी टेप करने की परियोजना स्वीकृत है किन्तु बाद में मस्तेमऊ में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण उपरान्त डायवर्जन कर दिया जायेगा।

गोमती नदी में गिरने वाले नालों पर, जिनका कैंवमेंट एरिया एच.एफ.एल. से नीचा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, वर्तमान में आवासीय/व्यवसायिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु विकसित किए गये हैं या किये जा रहे हैं, यथा शक्तिनगर, संजय गांधी पुरम, महानगर, गोमती नगर फेज-1 का भाग एवं गोमती नगर विस्तार आदि, के बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण की स्थिति एवं संचालन व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया, कि गोमती नदी में गिरने वाले 20 नालों को टेप करने एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण प्रक्रिया में है अथवा हो चुके है।

स्थापित बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता, व्यवस्था एवं संचालन की स्थिति संलग्नानुसार है।

गोमती नगर विस्तार योजना के लिए बाढ़ पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि विश्वास खण्ड एवं डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क के मध्य से गुजरने वाले कुकरैल नाले को टेप करने की व्यवस्था है अथवा नहीं, अवगत कराया गया कि सम्भवतः छूट गया है। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा सुझाव दिया गया कि इसे भी टेप कर लिया जाय।

गोमती नगर फेज-1 एवं फेज-2 में कॉन्टैमिनेट स्थलों पर जलभराव के समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। उनके कारणों एवं निदान का अध्ययन पुनः करा लिया जाये और समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

गोमती नगर की ड्रेनेज व्यवस्था ग्वारी कल्वर्ट से है। महाप्रबन्धक, 30प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि इस नाले को ग्वारी कल्वर्ट पर निर्मित होने वाले मेन पम्पिंग स्टेशन में टेप कर दिया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा गोमती नगर योजना में प्रस्तावित ड्रेनेज व्यवस्था को टेप करने फलड पम्पिंग स्टेशन बनाने एवं बैरल के निर्माण के सन्दर्भ में तत्काल कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी। अधिशासी

अभियन्ता, जोन-1 द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम व सिंचाई विभाग में सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित विभाग के साथ सम्पर्क कर शीघ्रता कराने का निर्देश दिया गया है।

कानपुर रोड योजना की ड्रेनेज व्यवस्था के निस्तारण में अवरोधों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। अधि० अभि० जोन-13 द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा किला मोहम्मदी ड्रेन को सुदृढ़ करने की परियोजना अन्तिम चरण में है और इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद सम्भवतः ड्रेनेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

जानकीपुरम् विस्तार एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये मुख्य नाले के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी। अधि० अभि० से निर्मित होने वाले नाले अथवा वर्तमान में स्थित नाले को सीधे गोमती नदी में गिराये जाने की स्थिति की जानकारी चाही गई। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उ०प्र० जल निगम व क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि गोमती एक्शन प्लान द्वितीय में स्वीकृत अन्ततः डिस्पोजल की स्थिति से अवगत कराया जाय। सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य आई.आई.एम. तक प्रस्तावित प्राधिकरण की नयी योजना के सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी। महाप्रबन्ध, उ०प्र० जल निगम, गोमती एक्शन प्लान द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ महायोजना 2021 की ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिये सम्मिलित प्रस्ताव में ड्रेनेज व सीवरेज व्यवस्था को ककरहा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट में निस्तारित, शुद्धीकृत करने का प्रस्ताव महायोजना में है। तदनुसार इन प्रस्तावित सेवाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था व कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी।

वसंत कुंज योजना व कैम्पबेल रोड की ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था को प्रभावी रूप में लाने हेतु सम्पवैल एवं पम्पिंग स्टेशन का निर्माण वसंतकुंज योजना में प्रस्तावित है। योजना के विरचन का कार्य प्राधिकरण व जल निगम, जल संस्थान द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कराया जा रहा है। जिसे अगले पंद्रह दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने का आश्वासन महाप्रबंधक जल निगम द्वारा दिया गया है।

कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, मानसरोवर योजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के स्थल भूमि के चयन हेतु दिनांक 06.07.06 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जल संस्थान, जल निगम एवं ल०वि०प्र० के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया, महायोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिये प्रस्तावित स्थल को उपयुक्त पाया गया। भू-अर्जन की तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

महानगर योजना के सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य दशकों से ल०वि०प्र० द्वारा किया जा रहा है, इसे जल संस्थान को हस्तांतरित करने पर चर्चा की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि अधिशासी अभियन्ता, जोन-10 को काफी समय पूर्व कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। अधि० अभि०-10 से अपेक्षा की गयी कि संयुक्त निरीक्षण करते हुये पम्पिंग स्टेशन को मानक के अनुसार विकसित कर तत्काल हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाय।

अलीगंज, जानकीपुरम् एवं संबंधित क्षेत्र के लिये अलीगंज योजना में संयुक्त रूप से पम्पिंग स्टेशन वर्ष 1998-99 से पूर्व निर्मित किया गया तभी से इसका संचालन

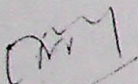
ल0वि0प्रा0 द्वारा किया जा रहा है। जब परियोजना पूर्ण हुयी थी तो जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए थी; ऐसा न करने पर मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 द्वारा खेद व्यक्त किया गया। सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियन्ता को 2 माह पूर्व पम्पिंग व्यवस्था को जल संस्थान को हस्तांतरित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अधि0 अभि0, जून-15 तथा अधि0 अभि0, जून-10 बैठक में उपस्थित नहीं थे, उनसे अपेक्षा की गयी कि पम्पिंग स्टेशन का संचालन मानक अनुसार करते हुये जल संस्थान को हस्तांतरित करायें।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान द्वारा नगर की पेयजल व्यवस्था में आये दिन आने वाली समस्याओं पर चिन्ता व्यक्त की गयी और अवगत कराया गया कि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत जनसंख्या को ही भूतल-पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद की योजनाओं में भूगर्भ-जल स्रोत ही एक मात्र पेयजल का स्रोत है, जिसके कारण भूजल स्तर तीव्रता से नीचे गिरता जा रहा है, अधिकांश ट्यूबवेलों की क्षमता कम होती जा रही है और नगर की बढ़ती जनसंख्या को वांछित पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार ट्यूबवेल है और कहीं पर आवश्यकतानुसार नहीं है, यह विषमता भी जनता के आक्रोश का कारण है।

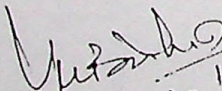
गत बैठक में इस समस्या पर चर्चा की गयी थी। स्रोत की उपलब्धता, जलकल संस्थान (वाटर वर्क्स) की व्यवस्थाओं और उससे पेयजल क्षेत्रों का निर्धारण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किये जाने की अपेक्षा की गई थी। मुख्य रूप से भूतल पेयजल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी आवश्यक है। जलकल तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम के लिये भूतल जल स्रोत पर विचार-विमर्श हेतु सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, आवास विकास परिषद व लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं की बैठक कर विस्तृत चर्चा करते हुये प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया गया।

महाप्रबन्धक, जल संस्थान से अनुरोध किया गया कि यथाशीघ्र बैठक की सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं वर्तमान में जल की उपलब्धता एवं जल आवश्यकता पर सम्पूर्ण विवरण तैयार कर लिया जाए, ताकि बैठक में पेयजल की आवश्यकता, भूतल जल स्रोत की उपलब्धता, जलकल के निर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

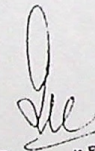
उपस्थित सदस्यों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुयी।


(आर.के. त्रिपाठी)

महाप्रबन्धक,
जल संस्थान


(बी.यू. चन्द्रा)

महाप्रबन्धक,
गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ0प्र0 जल निगम


(डी.आर. यादव)

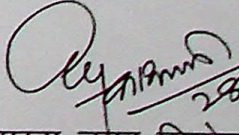
मुख्य अभियन्ता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय: बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के संबंध में।

प्रस्ताव:

महायोजना-2001 में बादशाह नगर स्टेशन के सामने वाली पटरी एवं स्टेशन के प्रवेश मार्ग से लगी हुई पटरी का भू-उपयोग व्यवसायिक प्रस्तावित किया गया था जिसे महायोजना-2021 में आवासीय में प्रस्तावित कर दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में शासन के पत्र संख्या: 4301/आठ-3-2005-31एल.यू.सी./2005 दिनांक: 21.12.2005 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./96 दिनांक: 13.10.98 के प्राविधानों के अनुसार निर्णय लिये जाने तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत दिनांक: 06.10.2005, जोकि तलपट मानचित्र में भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में है, के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाये।

शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक: 06 जनवरी, 2006 में विषय सं0-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त बैठक में सम्यक "विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गयी जिसमें अन्य सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे। यह समिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।" उक्त निर्णय के अनुपालन में समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि लखनऊ महायोजना-2001 तथा 2021 के अनुसार भूखण्ड सं0-4 आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार भी भूखण्ड सं0-4 का भू-उपयोग आवासीय निर्धारित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में शासनादेश सं0: सीएस-89(1) दि0: 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने संबंधी आदेश भी निर्गत किये गये हैं। समिति की उपरोक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


मुख्य नगर नियोजक

3
24

30

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7 - बन्दरियाबाग, लखनऊ

पत्रांक: 1019 / वनि(3) / लखनऊ वि.प्रा.-बैठक / 2006-07

दिनांक: मई, 2006

सेवा में,

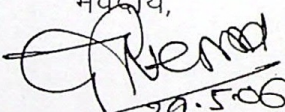
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय: बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 571/सीटीपी/2006 दिनांक 21.04.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के विषय संख्या-28 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों/अभिलेखों, लखनऊ महायोजना तथा स्थानीय स्तर पर परीक्षणोंपरान्त तैयार की गई आख्या एवं संस्तुति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एन.आर. वर्मा)
29.5.06

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की आख्या

प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में विषय संख्या-28 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसपर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश 'सदस्य' तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के 'संयोजक' नामित हैं। उक्त समिति से स्थल निरीक्षण के उपरान्त संस्तुतियाँ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा है।

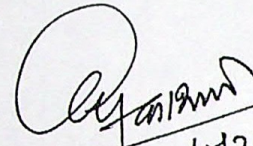
2. प्राधिकरण बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं, लखनऊ महायोजना, 2021, स्थानीय परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण के क्रम में आख्या एवं संस्तुति निम्नवत् है :-

- (1) भूखण्ड सं.-4 फैजाबाद मार्ग से माउन्ट कार्मेल स्कूल को जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इसी भूखण्ड के दक्षिण में फैजाबाद मार्ग से सटा हुआ भूखण्ड सं. 4-ए स्थित है। स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि संलग्न साइट प्लान के अनुसार भूखण्ड सं. 4-ए (कार्नर प्लॉट) में व्यवसायिक कामप्लेक्स निर्मित एवं कार्यरत है, जिसका मानचित्र लखनऊ महायोजना, 2001 के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के परमिट सं. 12371, दिनांक 20.09.2005 द्वारा स्वीकृत है। इसके पश्चात् बगल के अगले भूखण्ड में महानगर गर्ल्स इण्टर कालेज स्थित है, जिसके पश्चात् एक आवासीय भवन है तथा आवासीय भवन के बाद मस्जिद है। उक्त कालेज व मस्जिद के भूखण्ड के साथ मार्ग विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ छोटी दुकाने एवं अस्थायी निर्माण (मोटर गैराज आदि) मौजूद हैं। इन भूखण्डों के पृष्ठ भाग में पूर्णतः आवासीय भवन स्थित हैं।
- (2) लखनऊ महायोजना, 2001 तथा 2021 के अनुसार भूखण्ड संख्या-4 आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित है। यह भी उल्लेखनीय है कि महायोजना, 2021 के प्रारूप पर आमंत्रित आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई के उपरान्त हुए निर्णयों के क्रम में ही इस क्षेत्र में भू-उपयोग प्रस्तावित किये गए थे और तदनुसार शासन द्वारा लखनऊ महायोजना, 2021 को अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या-4 का भू-उपयोग आवासीय निर्धारित है तथा वर्तमान में भी आवासीय उपयोग में प्रयुक्त हो रहा है।
- (3) लीज डीड के अनुसार भूखण्ड सं.-4 का 1872 वर्ग फीट क्षेत्रफल व्यवसायिक उपयोग के अन्तर्गत उल्लिखित है, परन्तु शेष क्षेत्र की लीज डीड उपलब्ध न होने के कारण यह पुष्टि सम्भव नहीं है कि लीज डीड के अनुसार इसका क्या उपयोग है? अतः इसके सम्बन्ध में भी प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर ली जाये। यदि उक्त भूखण्ड नजूल भूमि पर है, तो नियमानुसार पट्टागत नजूल भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन विचारणीय नहीं है।

::2::

- (4) विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में शासनादेश सं. सी. एस.-89(1) / 9- आ -3-2003-62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू उपयोग में चल रही व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए विचार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त टिप्पणी/आख्या प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।


29/5/2006

(सी० पी० शर्मा)
मुख्य वक्ता नियोजक

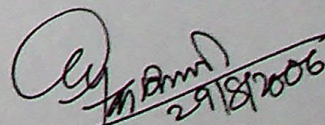
विषय: ग्राम-हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

महायोजना-2021 में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु लगभग 650 हेक्टेअर भूमि ग्राम-हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ, मस्तेमऊ एवं बतकास में प्रस्तावित की गयी है गोमती नगर विस्तार योजना से लगी हुई यह भूमि कतिपय सीवेज फार्म एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि -

1. सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये जो भूमि महायोजना में प्रस्तावित की गयी है वह गोमती नगर विस्तार योजना एवं उसके समीप निजी क्षेत्र की सहभागिता से विकसित की जा रही आवासीय योजनाओं से लगी हुई है, अतः पर्यावरण के दृष्टिकोण से उक्त स्थल सीवेज फार्म के लिये उपयुक्त नहीं होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर कई ग्रामीण आबादी हैं तथा उनके आस-पास भी काफी विकास हो चुका है। अतः सीवेज फार्म का निर्माण उक्त क्षेत्र में सम्भव नहीं है।
3. जल निगम द्वारा सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जायका कन्सल्टेन्ट से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है, उस प्रोजेक्ट में उपरोक्त प्रयोजन हेतु जो भूमि चयनित की गयी है वह प्रश्नगत क्षेत्र से बाहर है एवं गोमती नगर विस्तार योजना के प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

महायोजना-2021 में प्रस्तावित उपरोक्त वर्णित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू-उपयोग को आवासीय में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत परिवर्तित करने एवं उपरोक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


मुख्य नगर नियोजक



विषय : गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवंटन।

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। पार्क के मध्य में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थित है। इस उपकेन्द्र की स्थापना के लिए वर्ष 1990 में 39300 वर्ग मी0 भूमि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को आवंटित की गयी थी। सम्प्रति लोहिया पार्क के विकास के फलस्वरूप उक्त विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है। विद्युत उपकेन्द्र के स्थानान्तरण के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इसे उच्चीकृत किए जाने पर विचार उपयुक्त होगा।

गोमती पार के क्षेत्रों के विकास एवं इस ओर गोमती नगर योजना, इन्दिरा नगर योजना व अन्य आवासीय क्षेत्रों के विकास एवं अध्यासन के फलस्वरूप विद्युत मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 उपकेन्द्र को मांग के अनुरूप उच्चीकृत करते हुए अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाए जाने का प्रस्ताव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को प्रेषित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान उपकेन्द्र में पदस्थ स्टाफ के लिए नेहरू इन्क्लेव में प्रेमायन-1 प्रकार के 6 फ्लैट आरक्षित किए गए हैं तथा 220 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना के लिए गोमती नगर विस्तार योजना में 10 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की शिफ्टिंग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस विषय पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.06 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूमि की देयता के संबंध में शासन का जो भी निर्णय होगा वह सभी पक्षों को मान्य होगा साथ ही पावर कारपोरेशन को आवंटित किए गए 6 फ्लैट्स के मूल्य, तोड़े गए भवनों एवं अर्द्धनिर्मित कार्यालय के मुआवजे के संबंध में भी यह निर्णय हुआ कि शासन द्वारा लिया गया निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा। इस बिन्दु पर निर्णय होने की प्रतीक्षा किए बिना उपकेन्द्र को उच्चीकृत करने व स्थानान्तरित करने का कार्य पावर कारपोरेशन द्वारा प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा नेहरू इन्क्लेव योजना में आरक्षित किए गए भवनों का मूल्य पृथक से सूचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था जबकि गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए आवासीय दर के 50 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटित की गयी है तथा तत्काल कार्य प्रारम्भ करने के दृष्टिकोण से प्राधिकरण द्वारा पावर कारपोरेशन को भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

अतः डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में देयता का निर्धारण किए जाने हेतु शासन के निर्णय के लिए प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(Signed) Bhatia/July, 06/Without Upk.cenr.doc

मुख्य अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण

2046/106

383/106

25-3-06

22-3-06

अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की अध्यक्षता में दिनांक 18-3-2006 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

1460/106

27-03-2006

उपस्थिति :

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ विकास प्राधिकरण

- 1- श्री ए०के० खुराना, अध्यक्ष
- 2- श्री बी०बी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०
- 3- श्री कृष्ण कान्त, मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण)
- 4- श्री डी०वी०एस० रावत, महाप्रबन्धक (जानपद पारेषण)
- 5- श्री अशोक कुमार, उप महाप्रबन्धक विद्युत पारेषण मण्डल-प्रथम, लखनऊ

- 1- श्री बी०बी० सिंह, उपाध्यक्ष
- 2- श्री रोहित खन्ना, अधिशासी अभियन्ता

1- प्रस्तावित 220/33 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण हेतु एल्लिको ग्रीन के पीछे स्थित ग्रीन बैल्ट में से 10 एकड़ भूमि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि चिन्हित भूमि का कब्जा उ०प्र. पावर कारपोरेशन लि० को दिनांक 25-3-2008 को दिला दिया जायेगा। जहाँ तक भूमि की देयता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह सहमति बनी कि इस विषय में शासन का जो भी निर्णय होगा, वह सभी पक्षों को मान्य होगा।

2- 132 के०वी० उपकेन्द्र गोमतीनगर पर स्थित उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के 8 आवासों एवं मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण) के कार्यालय के अर्धनिर्मित भवन को तोड़ दिया गया था, के एवज में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू इन्वलेव स्थित प्रेमायन -1 में 8 फ्लैट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को आवंटित कर दिये गये हैं। इन भवनों के मूल्य एवं तोड़े गये भवनों एवं अर्धनिर्मित कार्यालय के मुआवजे के सम्बन्ध में शासन का जो भी निर्णय होगा, वह भी सभी पक्षों को मान्य होगा।

3- किसी भी विवाद की स्थिति में निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं विवाद के सम्बन्ध में जो भी शासन का निर्णय होगा वह सभी पक्षों को मान्य होगा।

(कृष्ण कान्त)

मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण)
दिनांक : मार्च 21, 2006

संख्या 643 मु०ग०प्र० (पा०) /

प्रतिलिपि :

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 3- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ।
- 5- महाप्रबन्धक (जानपद पारेषण) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक (पारेषण) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 7- उप महाप्रबन्धक, विद्युत, पारेषण मण्डल, लखनऊ।
- 8- श्री रोहित खन्ना, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक:- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संख्या: 138/एनकेसीएल/06 दिनांक: 24-4-06	सेवा में, श्री अशोक कुमार खुराना, अध्यक्ष, उ0प्र0पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ। नत्थी
---	--

विषय

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-6 में 220 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उच्चस्तर पर हुये विचार विमर्श का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। योजना में 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हेतु चिन्हित भूमि का सर्वेक्षण एवं प्राथमिक निरीक्षण प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, मुख्य महाप्रबन्धक, परिषण, महाप्रबन्धक, लेसा व अधिशासी अभियंता, परिषण द्वारा दिनांक 23.4.2006 को किया जा चुका है। उक्त के कम में उपकेन्द्र की स्थापना हेतु 10 एकड भूमि आवंटित की जाती है, जिसका प्लान संलग्न है। 10 एकड भूमि का मूल्य रू0 2000.00 प्रतिवर्गमीटर (आवासीय दर रू0 4000.00 का 50 प्रतिशत) की दर से रू0 8,09,37,200.00 होता है, इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क रू0 97,12,464.00 एवं वाटर सीवर तथा अन्य व्यय रू0 3500.00 कुल धनराशि रू0 9,06,53,164.00 दिनांक 31.5.2006 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शेष नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

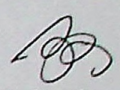
- 1- भू-आच्छादन एफ0ए0आर0 एवं भू-प्रयोग महायोजना/शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 2- भूमि जहाँ है जैसी है के आधार पर दी जायेगी।
- 3- उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भूमि की वास्तुविक नाप कराई जायेगी और यदि कोई अन्तर की धनराशि देय होगी तो वह निबन्धन से पूर्व ली जायेगी तथा भूमि के निबन्धन हेतु निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण के संबंध में जो व्यय होगा वह विभाग द्वारा वहन करना होगा।
- 5- उपरोक्त तिथि तक धनराशि प्राप्त न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6- यदि भविष्य में प्रतिकर की धनराशि में कोई बढोत्तरी मा0 न्यायालय द्वारा की जाती है तो बढे हुये प्रतिकर का भुगतान विभाग द्वारा करना होगा।

-2-

- 7- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा जो शर्तें निर्धारित की गयी हैं/की जायेंगी वह मान्य होंगी।
- 8- बैंक ड्राफ्ट सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।
- 9- उपरोक्त गणना अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर की गयी है लीज प्लान प्राप्त होने के पश्चात अन्तिम गणना करायी जायेगी, जो मान्य होगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

 24/5
(बी०बी० सिंह)
उपाध्यक्ष।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

भवदीय,

/
(बी०बी० सिंह)
उपाध्यक्ष।

विषय : गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मंजिले ब्लॉक्स का निर्माण कार्य।

गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पर 8 मंजिले भवनों के निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1994 में तैयार किया गया था। प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए ले-आउट प्लान में कुल 10 ब्लॉक्स के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। अवध अपार्टमेन्ट हेतु आर्कीटेक्ट के चयन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष बैठक दिनांक 6.12.96 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में यह अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्लान के आधार पर अवध अपार्टमेन्ट योजना का पंजीकरण वर्ष 1994 में खोला गया था। इसके अंतर्गत केनरा बैंक व यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा बल्क पंजीकरण कराया गया तथा प्राप्त पंजीकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक श्रेणी के भवनों के एक-एक ब्लॉक (कुल तीन ब्लॉक) का निर्माण किया जाए।

विपुल खण्ड में ग्रुप हाउसिंग हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का अंश भाग रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को बल्क में विक्रीत किए जाने के फलस्वरूप अवध अपार्टमेन्ट योजना में बहुमंजिले भवनों के निर्माण के लिए कुल 13642 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हैं। इस परिसर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी तत्समय ही किया जा चुका है। वर्ष 1996 में उपलब्ध पंजीकरणों की संख्या के आधार पर केवल 3 ब्लॉक्स के निर्माण विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवनों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव एवं आर्कीटेक्ट के चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 1996 में कहकशां, आफताव एवं फिरदौस नाम के तीन ब्लॉक का निर्माण किया गया जिसमें क्रमशः तीन बेडरूम, दो बेडरूम व एक बेडरूम के फ्लैट्स निर्मित हैं। निर्मित किए गए भवनों का निबंधन कर अधिकांश भवनों का कब्जा आवंटियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। कहकशां ब्लॉक के 23 भवनों का कब्जा हस्तान्तरित किया जाना शेष है।

केनरा बैंक व यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा बल्क में क्रय किए गए भवनों के निबंधन विलेख में यह अंकित किया गया था कि भवनों का निबंधन अविभाजित भूमि के समानुपातिक भाग के साथ किया जा रहा है। निबंधन विलेख में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि समानुपातिक अंश का क्या तात्पर्य है। अतः इस संबंध में केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया व कुछ आवंटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर नए ब्लॉक का निर्माण रोके जाने का अनुरोध किया गया है। वाद की सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश परित नहीं किए गए हैं। मा0 न्यायालय के समक्ष भी यह स्पष्ट किया गया है कि अविभाजित भूमि के समानुपातिक अंश का तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्रफल से है जोकि अनुमन्य एफ.ए.आर. हेतु आवश्यक होगा। भविष्य में पुनः यह स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए आवश्यक है कि निष्पादित निबंधन विलेख में उक्त

lc

3

9

संशोधन कर दिया जाए तथा भविष्य में किए जाने वाले निबंधनों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि समानुपातिक भूमि का तात्पर्य एफ.ए.आर. के अनुपात में भूमि से है।

सम्प्रति परियोजना में दो नए ब्लॉक के निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अनुमत्य एफ.ए.आर. तथा भू-आच्छादन के आधार पर कुल 12 मंजिले भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना में पूर्व निर्मित तीन ब्लॉक तथा वर्तमान में प्रस्तावित दो नये ब्लॉक का सम्मिलित प्लान संलग्नक-1 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

भवन का प्रकार	प्राविधान	प्रस्तावित संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य
श्रेणी 1	3 बेडरूम	60	रु0 27,80,000.00
श्रेणी 2	2 बेडरूम	12	रु0 22,02,000.00

अनुमोदित प्रस्ताव के आधार पर भवनों का पंजीकरण खोला गया जिसके क्रम में श्रेणी 1 प्रकार के भवनों के लिए कुल 12 आवेदन तथा श्रेणी 2 प्रकार के भवनों के लिए कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयकर विभाग एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बल्क आवंटन के अंतर्गत श्रेणी 1 प्रकार के तीन बेडरूम वाले भवनों के आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। दो बेडरूम के फ्लैट के लिए पर्याप्त मांग नहीं है, अतः तीन बेडरूम के फ्लैट हेतु उपलब्ध मांग के आधार पर योजना में तीन बेडरूम वाले फ्लैट्स के एक ब्लॉक के निर्माण का प्रस्ताव है तथा भविष्य में और मांग होने पर दूसरे ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा।

बहुवर्षीय भवनों के नियोजन व सर्विसेज डिजाइनिंग का कार्य विशेष प्रकृति का कार्य है जिसके लिए अनुभवी आर्किटेक्ट्स का पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। अतः विशेष प्रकृति की इस परियोजना के नियोजन के लिए निजी वास्तुविद् को अनुबंधित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत परियोजना के नियोजन, डिजाइनिंग व स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि कार्य के लिए निजी वास्तुविद् मे0 आर्किटेक्ट एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को 2 प्रतिशत की दर से फीस के आधार पर अनुबंधित किया गया है।

अतः गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट में दो नए ब्लॉक के निर्माण एवं इनकी डिजाइनिंग के कार्य हेतु आर्किटेक्ट मे0 आर्किटेक्ट एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को अनुबंधित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

3

OTHER'S PROPERTY

THIS IS AN ORIGINAL, UNPUBLISHED WORK AND PROPERTY OF MS ARCHITECTS AND ASSOCIATES NEW DELHI. THIS MAY NOT BE PUBLISHED, MISUSED, TEMPERED AND DUPLICATED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE ARCHITECTS.

NOTES:-

1. SITE PLAN AS PER DIMENSIONS PROVIDED BY LDA
2. LOCATION OF EXISTING BUILDING NO 1,345 ARE AS PER DETAILS PROVIDED BY LDA. THE DIMENSIONS & AVAILABILITY TO BE CHECKED BEFORE FINILISING THE LAYOUT OF BLOCKS 2,4,6.

24 M WIDE ROAD

30 M WIDE ROAD TO SAHARA SHAHAR

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN

AVADH APARTMENT

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
GOMTI NAGAR,LUCKNOW.

DISTRIBUTIONS

2-1-06

MAIL TO ANAND HAVEJA

NO

DATE

REVISIONS

ARCHITECTS REKHA RAJIV
ARCHITECTS AND ASSOCIATES

A-262,NEW FRIENDS COLONY,NEW DELHI-65

Ph: 011-26046113,51629572 TEL/FAX:011-26823763

e-mail: rekharajiv@rediffmail.com



DEALT-NAGI

DRG NO C-5 496 -B

DATE : 01-01-06 SCALE : 1:600

WORKING DRAWING

SITE PLAN



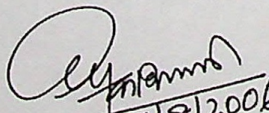
विषय: एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के संबंध में।

प्रस्ताव:

पूर्व में महानगर लखनऊ में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं स्वीकृत योजनाओं में आवासीय भूखण्डों पर एकल आवासीय भवन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान था तथा प्राधिकरण की योजनाओं में इस हेतु लीज डीड अथवा फ्री-होल्ड डीड में यह अंकित भी किया जाता रहा है। एकल आवासीय भवन का तात्पर्य छोटे भूखण्डों पर न्यूनतम एक कमरा, किचन, ट्वालेट तथा बड़े भूखण्डों पर न्यूनतम दो कमरे, किचन, ट्वालेट के निर्माण से है जैसा कि फ्री-होल्ड के शासनादेश संख्या: 1639/9-आ-1-65-80मिस/86 दिनांक: 10.05.1995 तथा शासनादेश संख्या: 1778/9-अ-95-213डी.ए./94 दिनांक: 24.05.1995 से स्पष्ट है।

भवन उपविधि-2000 के अन्तर्गत 1000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय यूनिट, प्रभार रहित व प्रभार सहित दिये जाने का प्राविधान किया गया। तथा 1000 वर्गमीटर से ऊपर ग्रुप हाउसिंग का प्राविधान था किन्तु ग्रुप हाउसिंग प्राविधान संशोधित होने के उपरान्त ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो गया (शासनादेश संख्या: 3001/9-आ-3-2001/19विविध/2001(आ.ब.) दि०: 29.8.2002), ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड एकल आवासीय भवन की श्रेणी में आ जाने के कारण भूमि के आप्टीमम् उपयोग के दृष्टिगत 500 वर्गमीटर से 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों हेतु प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों के प्राविधान शासन द्वारा शासनादेश संख्या: 553 दिनांक: 25.01.03 द्वारा जारी किये गये, जिसके अनुपालन में प्रदेश में आवासीय इकाईयों दी जाने लगीं। आवासीय इकाईयों के दिये जाने के विरोध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर गाजियाबाद के निवासी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर वाद संख्या: 2342/2004 आई.सी.अग्रवाल बनाम डी.पी.सिंह उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य में निर्णय के फलस्वरूप पुनः शासनादेश फरवरी, 2005 जारी किया गया जिसमें उपविधि में अंकित एकल आवास को प्लॉटेड विकास से प्रतिस्थापित किया गया तथा प्रभार सहित व प्रभार रहित इकाईयों दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण हेतु भी आदेशित किया गया। प्राधिकरण की बहुत पुरानी योजनाएँ जैसे- महानगर, निराला नगर, न्यू हैदराबाद आदि में बहुत बड़े-बड़े भूखण्ड हैं जिनका आकार 500 वर्गमी० से 2000 वर्गमी० के अन्दर है, पर वर्तमान में भू-स्वामियों द्वारा बढ़ती आवश्यकता एवं बेहतर रिहायश के दृष्टिगत यूनिट हेतु आवेदन दिये गये हैं।

अतः प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत पुरानी योजनाओं में प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाईयों दिये जाने हेतु स्थान चिन्हिकरण शासनादेश संख्या: 885/आठ-1-05-29विविध/98(आ.ब.) दिनांक: 09.02.2005 के क्रम में प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं जैसे-महानगर, निरालानगर, न्यू हैदराबाद आदि में अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


17/8/2006
(सी० बी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु पुस्तिका

शासनादेश सं० १६३६/६-अ-१-६५-८० मिस/८६ दि० १०-५-६५ तथा शासनादेश सं० १७७८/६-अ-६५२१३ डी.ए./६४ दि० २४-५-६५ द्वारा शासन ने विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनों/भूखण्डों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु निर्णय लिया है। अतः संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है :-

१. उपरोक्त शासनादेश इस पुस्तिका में अंकित है।
२. उपरोक्त पुस्तिका में दिये हुए आवेदन पत्र पर आवंटी लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु अपना आवेदन देगा।
३. आवेदन पत्र के साथ आवंटी को एक शपथ पत्र, जिसका प्ररूप इस पुस्तिका में दिया हुआ है, संलग्न करना होगा। यह शपथ पत्र रु० १०/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
४. यदि पूर्व में वर्षवार लीज रेन्ट जमा किया गया है तो दि० ३१-३-६६ तक का अवशेष लीज रेन्ट एवं भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १२ प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो सचिव, ल० वि० प्रा० के पक्ष में हो, आवेदन पत्र के साथ जमा किया जायेगा। यदि लीज डीड के निष्पादन से पूर्व भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत जमा किया जा चुका है तो रजिस्ट्रेशन मूल्य का २ प्रतिशत और जमा करना होगा।
५. जिन आवंटियों द्वारा लीज डीड के निष्पादन से पूर्व भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत लीज रेन्ट के रूप में पहले ही जमा कर दिया गया था और उन्होंने २ प्रतिशत और जमा कर दिया है तो ऐसे आवंटी को रजिस्ट्रेशन मूल्य के उपरोक्तानुसार दो प्रतिशत पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार से ट्रेजरी से स्टाम्प पेपर क्रय करना होगा तथा पुस्तिका में दिये हुए विक्रय विलेख को स्टाम्प पेपर पर टंकित करा ले ऐसे प्रत्येक आवंटी को तीन प्रतियां टंकित करानी होगी- एक स्टाम्प पेपर पर तथा दो प्रतियां वाटर मार्क पर। यह तीनों प्रतियां आवंटी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।
६. जिन आवंटियों ने उपरोक्त क्रम सं०-५ के अनुसार भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का १० प्रतिशत लीज रेन्ट जमा नहीं किया था और अब रजिस्ट्रेशन मूल्य का १२ प्रतिशत जमा किया है तो ऐसे आवंटी को रजिस्ट्रेशन मूल्य के उपरोक्तानुसार १२ प्रतिशत पर देय स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार ट्रेजरी से स्टाम्प पेपर क्रय करना होगा तथा पुस्तिका में दिये हुए विक्रय विलेख को स्टाम्प पेपर पर टंकित करना होगा। ऐसे प्रत्येक आवंटी को तीन प्रतियां टंकित कराना होगा - एक प्रति स्टाम्प पेपर पर तथा दो प्रतियां वाटर मार्क पर। यह तीनों प्रतियां आवंटी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा।
७. आवंटी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र भरकर तथा उसके साथ संलग्नक लगाकर यूको

बैंक की हजरतगंज शाखा, विस्तार पटल शाखा, ल०वि०प्रा० कार्यालय में प्रत्येक कार्यादिवस में प्रातः १०.३० बजे से अपरान्ह २.३० बजे तक जमा करेगा। इस पुस्तिका में जो चालान दिया हुआ है उस चालान को भी आवंटी को भरना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

- c. उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में आवंटी को यदि कोई कठिनाई महसूस हो तो वह ल०वि०प्रा० के जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
६. आवंटी द्वारा जो आवेदन पत्र फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा उसके अनुसार आवश्यक जांच संपत्ति विभाग में की जायेगी और यदि आवेदन पत्र में कोई कभी पायी जाती है तो इस संबंध में पत्र संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा आवंटी को भेजा जायेगा। निर्धारित अर्हतायें पूरी होने के पश्चात ही लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया जायेगा।
१०. यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी जाती है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरा अधिकार होगा कि वह लीज होल्ड भूमि से फ्रीहोल्ड में जो परिवर्तन किया गया है, उसे निरस्त कर दें। आवंटी द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि को जब्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कार्यवाही जो उपाध्यक्ष ठीक समझे, कर सकते हैं।
११. "निष्पादित लीज डीड के प्राविधानों के अनुसार जिन आवंटियों ने आवंटित भूखण्ड पर निर्धारित अवधि में निर्माण न कराया हो तो ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात शासनादेश के अनुसार अनिर्माण शुल्क (लेवी) देयी होगी। वर्ष के भाग को पूरा वर्ष लेवी के लिये माना जायेगा। शासकीय विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लेवी देय नहीं होगी।"

- टिप्पणी : (१) २०० व. मी. तक के भूखण्ड पर एक कमरा, एक टायलेट एवं एक किचेन बन जाने पर निर्मित माना जायेगा।
- (२) २०० व. मी. से ऊपर के भूखण्ड पर दो कमरे, एक टायलेट एवं एक किचेन के निर्माण को निर्मित माना जायेगा।
१२. उपरोक्त परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में उपाध्यक्ष, ल० वि० प्रा० का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।



सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

98-8/20

37

14/2/05

संख्या : 888/आठ-1-05-29विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

जे.एस. मिश्र,
सचिव,

कार्यालय, ल. वि. शा.

संख्या 1376/699 उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक 14/2/05

सोमती

PA

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 08 फरवरी, 2005.

विषय :- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 एवं सुसंगत शासनादेशों में 'एकल आवासीय भवन' की परिभाषा में स्पष्टीकरण/संशोधन तथा उन्हें लागू करने हेतु उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 में निहित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा अबमानना याचिका संख्या : 2342/2004 आई.सी. अग्रवाल बनाम डी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में दिनांक 16.09.04 को पारित आदेशानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में 'एकल आवासीय भवन' की दी गई परिभाषा के दृष्टिगत उक्त उपविधि के प्रस्तर : 3.5.1 एवं सुसंगत शासनादेशों में 'एकल आवासीय भूखण्डों पर अनुमत्य एक से अधिक आवासीय इकाइयों को विरोधाभासी बताया गया है। वर्णित स्थिति में उक्त परिभाषा में स्पष्टीकरण/संशोधन एवं सुसंगत शासनादेशों में समरूप शब्दावली का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो गया है।

2- इस संबंध में 'एकल आवासीय भवन' की परिभाषा में इंगित विरोधाभास के निराकरण तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 553/9-आ-1-29विविध/98, दिनांक 25.01.03 के अधीन जारी संशोधनों को उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 में निहित प्राविधान के अनुसार लागू करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-

2.1 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-1 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में 'आवासीय भवन' की परिभाषा दी गई है एवं उसके अंतर्गत यह भी उल्लेख है कि 'एकल आवासीय भवन' का तात्पर्य आवासीय उपयोग हेतु एक भूखण्ड पर एक आवासीय भवन से है। जबकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-3, भाग-5 के प्रस्तर : 3.5.1 में 'एक आवासीय भवन' के स्थान पर 'आवासीय (प्लॉटड)' का उल्लेख है।

AVAS-I/GO-6

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या : 553/9-आ-1-29विविध /98, दिनोंक 25.01.03 तथा कतिपय अन्य शासनादेशों में भी 'एकल आवास' का उल्लेख है। इस प्रकार भवन उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों में 'आवासीय' हेतु अलग-अलग शब्द जी (यथा आवासीय जाटेड, एकल आवासीय भवन, एकल आवास) का प्रयोग किया गया है, जो कि विधिक रूप से समरूप होनी चाहिए।

आवासीय ले-आउट प्लान/योजना का नियोजन चूंकि दो पद्धतियों : 'प्लॉटेड डेवलपमेंट' तथा 'ग्रुप हाउसिंग' पर आधारित होता है, अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में दी गई आवासीय भवन की परिभाषा में से 'एकल आवासीय भवन' से संबंधित वाक्य को समाप्त किया जाता है एवं सुसंगत शासनादेशों में 'एकल आवासीय भवन/एकल आवास' को 'भूखण्डीय विकास' (प्लॉटेड डेवलपमेंट) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2.2 शासनादेश संख्या : 3001/9-आ-3-01-19विविध/01, दिनोंक 29.08.02 द्वारा हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमी. से बढ़ाकर 2000 वर्गमी. कर दिये जाने के फलस्वरूप 1000 से 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भवन भूखण्डीय विकास की श्रेणी में आ गए हैं जिसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या : 553/9-आ-1-29विविध/98, दिनोंक 25.01.03 के प्रस्तर : 2.3 तथा 2.4 में 500 वर्गमी. से अधिक एवं 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु सेट बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं अनुमन्य इकाइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है।

उक्त शासनादेश दिनोंक 25.01.03 के प्रस्तर : 2.6 में यह उल्लेख है कि, 'विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निहित तथा पूर्व में जारी संगत शासनादेशों के प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।' इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भवन उपविधि में प्रस्तावित संशोधनों को विकास प्राधिकरणों द्वारा उप. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अनुसार बोर्ड में अंगीकृत करने एवं शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही लागू किए जाने का प्राविधान है। तदनुसार ही विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2.3 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 3002/9-आ-1-29विविध/98, दिनोंक 08.06.01 के अधीन कतिपय परिष्कार किए गए थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर : 28(ख) में यह अपेक्षा की गयी थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी योजनाओं जहाँ बड़े हुए धनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्द्धन/सुदृढीकरण सम्भव है अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर धनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है, को बोर्ड द्वारा चिन्हित करने के उपरान्त ही 'प्रभार रहित' एवं 'प्रभार सहित' इकाइयों अनुमन्य किए जाने से निज किया जाए। अतः विकास प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड स्तर से आवासीय भूखण्डों

(भूखण्डीय विकास) के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयों अनुमन्य किया जाना नियोजन एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

इस संदर्भ में शासन की अपेक्षा है कि विकसित/अनुमोदित योजनाओं में "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयों की अनुमन्यता से संबंधित प्राविधानों का क्रियान्वयन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति एवं उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त ही किया जाय।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर : 2.1, 2.2 एवं 2.3 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 में निहित प्राविधान के अनुसार विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकरण के पश्चात् एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था द्वारा यदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 तथा उससे संबंधित समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का विचलन/उल्लंघन किया गया हो अथवा भविष्य में किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अधीन तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- उपर्युक्त के संबंध में पूर्व में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएं।

भवदीय,

1/11/92

(जे.एस. मिश्र)

सचिव

संख्या : 886(1)/आठ-1-05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

[Signature]
(संजय भूसरेड्डी)

विशेष सचिव

भाग-5

भू-आच्छादन एवं एफ. ए. आर.

3.5.1^{8.0} भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक

(i) विभिन्न उपयोगों हेतु अधिकतम भू-आच्छादन तथा एफ. ए. आर. निम्नवत् होगा :-

क्रमांक	उपयोग समूह	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ. ए. आर.	निःशुल्क इकाईयाँ (संख्या)	अतिरिक्त इकाईयाँ (संख्या)	कुल इकाईयाँ (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय (प्लॉट/ड)					
	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)					
●	50 तक	75	2.0	2	—	2
●	51-100 तक	75	2.0	2	1	3
●	101-300 तक	65	1.75	3	2	5
●	301-500 तक	55	1.50	4	2	6
●	500 से अधिक	45	1.25	4	4	8
2	व्यवसायिक					
(क)	आवासीय क्षेत्र में					
(i)	सुविधाजनक दुकानें	60	1.2			
(ii)	विपणन केन्द्र/अन्य शॉपिंग केन्द्र					
(ख)	बाजार स्ट्रीट	40	1.2			
(ग)	महायोजना में चिन्हित वाणिज्यिक क्षेत्र	40	1.2			
	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)					
●	500 तक	50	1.5			
●	500-1000	40	1.75			
●	1000 से अधिक	30	2.0			
3.	कार्यालय	40	1.5			
	अथवा	30	2.0			

(3)

1.2.14 "उपयोग समूह" (यूज ग्रुप) का तात्पर्य अधिभोग के अनुसार भवन के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए मुख्य उपयोग से है, जिसके लिए भवन या भवन का कोई भाग प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत हो। अधिभोग में अनुसंगी अधिभोग भी सम्मिलित है। अधिभोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार :-

- (I) "आवासीय भवन" : के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। "एकल आवासीय भवन" का तात्पर्य आवासीय उपयोग हेतु एक भूखण्ड पर एक आवासीय भवन से है।
- (II) "शैक्षिक भवन" : के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कालेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु लोग एकत्र होते हों।
- (III) "संस्थागत भवन" : के अन्तर्गत वे सभी भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों यथा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य उपचार या भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल या दुर्बल शिशुओं की देखभाल या अरोग्य प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के रहने, वृद्ध व्यक्तियों अथवा दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरुद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान भी सम्मिलित हो। संस्थागत भवन में अस्पताल, सैनीटोरियम, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं और दण्डात्मक संस्थाएं यथा जेल, कारागार, मानसिक-चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी।
- (IV) "असेम्बली भवन" : इसके अन्तर्गत भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद-प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति सिविल ट्रेवल, नगरीय यात्रा तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो, उदाहरण स्वरूप नाट्यशाला, छविगृह, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, स्केटिंग, व्यायामशाला, नृत्य, गृह क्लब, यात्री स्टेशन, वायु, थल अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीड़ा स्थल आदि।

अंशतः भू-तल के तल के ऊपर आच्छादित निर्माण हो।

पर्य भवन के किसी तल

का तात्पर्य किसी भूखण्ड तल क्षेत्रफल को विभाजित

able FAR) का तात्पर्य न उपविधि में अनुमन्य मा तक अनुमन्य अतिरिक्त विहित शुल्क का भुगतान

satory FAR) का तात्पर्य रण अथवा जनसुविधाओं से प्राधिकरण को निःशुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु अवशेष अनुमन्य अतिरिक्त एफ.ए.

धिमुक्त या अधिभोग के लिए ह अध्ययन, आवास, शयन, सोई घर, स्नानगृह, शौचालय, ह और स्टोर रूम, कारीडोर अन्य स्थान, जो प्रायः आवास सम्मिलित नहीं होंगे।

बीच मध्यवर्ती ऐसे तल के बचे हुए स्थान से है जो हो और जिसे भण्डारण हो।

तल के ऊपर किन्ही दो तलों निचले तल से पहुँचा जा सके

2.5 महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य प्रकृति के बहुमंजिले निर्माण हेतु यदि स्थल निर्दिष्ट हों, तो वहाँ भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण अनुमन्य होगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्राविधान केवल नए स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर लागू होंगे, पूर्व स्वीकृत अथवा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लागू नहीं होंगे।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नगरों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/स्काईलाइन, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निषिद्ध क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से संरक्षण योग्य क्षेत्रों में "हाई-राईज" निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। अतः अपने-अपने नगरों में ऐसे स्थलों/क्षेत्रों को सड़क/रेलवे लाइन/नदी एवं नाले अथवा अन्य भौतिक आकृतियों से सीमांकित करते हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शासन के अनुमोदन हेतु एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि भवन उपविधि में तदनुसार आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किए जा सकें।

भवदीय,

Imu...

(जे. एस. मिश्र)

सचिव

संख्या 3001 (1)/9-आ-3-2001/19 विविध/2001(आ.ब.) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू. पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ. प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, 350, सेक्टर-28, नोएडा।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

29/8/2002
(संजीव कुमार)

विशेष सचिव

आवासीय ले-आउट प्लान/योजना का नियोजन चूंकि दो पद्धतियों : 'प्लॉटेड डेवलपमेंट' तथा 'ग्रुप हाउसिंग' पर आधारित होता है, अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में दी गई आवासीय भवन की परिभाषा में से 'एकल आवासीय भवन' से संबंधित वाक्य को समाप्त किया जाता है एवं सुसंगत शासनादेशों में "एकल आवासीय भवन/एकल आवास" को "भूखण्डीय विकास" (प्लॉटेड डेवलपमेंट) से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2.2 शासनादेश संख्या : 3001/9-आ-3-01-19विविध/01, दिनांक 29.08.02 द्वारा हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल : 1000 वर्गमी. से बढ़ाकर 2000 वर्गमी. कर दिये जाने के फलस्वरूप 1000 से 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के आवासीय भवन भूखण्डीय विकास की श्रेणी में आ गए हैं जिसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या : 553/9-आ-1-29विविध/98, दिनांक 25.01.03 के प्रस्तर : 2.3 तथा 2.4 में 500 वर्गमी. से अधिक एवं 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों हेतु सेट बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं अनुमन्य इकाइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है।

2.3 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या : 3002/9-आ-1-29विविध/98, दिनांक 08.06.01 के अधीन कतिपय परिष्कार किए गए थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर : 28(ख) में यह अपेक्षा की गयी थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी योजनाओं जहाँ बड़े हुए धनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का वर्द्धन/सुवृद्धीकरण सम्भव है अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर धनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है, को बोर्ड द्वारा चिन्हित करने के उपरान्त ही "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयों अनुमन्य किए जाने पर विचार किया जाए। अतः विकास प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड स्तर से योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण किए बगैर एकल आवासीय भूखण्डों (भूखण्डीय विकास) के अंतर्गत अतिरिक्त इकाइयों अनुमन्य किया जाना नियोजन एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

इस संदर्भ में शासन की अपेक्षा है कि पूर्व विकसित/अनुमोदित योजनाओं में "प्रभार रहित" एवं "प्रभार सहित" इकाइयों की अनुमन्यता से संबंधित प्राविधान का क्रियान्वयन प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों का चिन्हीकरण अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति एवं उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया को पूर्ण धनत्व के उपरान्त ही किया जाय।

3- अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी व्यक्ति/समूह/संस्था द्वारा यदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 तथा उससे संबंधित समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का विचलन/उल्लंघन किया गया हो अथवा भविष्य में किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अन्वीन

4- कृपया उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करा दी जाय तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(जे.एस. मिश्र) -

सचिव

संख्या : 2561(1)/आठ-1-05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. विकास प्राधिकरणों के समस्त उपाध्यक्षों को इस आशय से कि बिन्दु संख्या : 2.1, 2.2 एवं 2.3 में उल्लिखित संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में समायोजित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रामकृष्ण प्रसाद)
विशेष सचिव

प्रेमक,

जयपुर प्रताप सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष/
उपाध्यक्ष,
संयुक्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक ३ मई, 1996

विषय :- नगरों को महापंजीना के अन्तर्गत ग्राम हाउसिंग योजना के लिए अनुमत्य स्फोरओआरओ का पुनर्निर्धारण ।

महोदय,

नगरांच क्षेत्रों में ग्राम हाउसिंग पेटर्न पर आवासीय निर्माण हेतु भू-आच्छादन, स्फोरओआरओ तथा अधिकतम ऊंचाई आदि के लिए शासनादेश संख्या-438 5/37-5-89-2-आ-01/89, दि०-01-01-90 द्वारा मानक निर्धारित किए गये हैं । यह शासनादेश लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, अलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद नगरों के लिए अलग-अलग जारी किए गये हैं । इन सभी नगरों में स्थानीय विकास को स्थिति के अनुसार विकसित, अविकसित एवं विकासशील क्षेत्रों के लिए स्फोरओआरओ अधिकतम 2.5 से न्यूनतम 1.2 तक निर्धारित किया गया है ।

2- स्फोरओआरओ के उक्त निर्धारण में भूमि के मूल्य को दृष्टिगत नहीं रखा गया जिसके कारण इन नगरों की महापंजीना में ग्राम हाउसिंग हेतु निर्धारित स्फोरओआरओ कार्यालय के लिए निर्धारित स्फोरओआरओ से अधिक हो गया है । कार्यालय आवासीय भू-उपयोग की अपेक्षा तथ्य भू-उपयोग है । अतः ग्राम हाउसिंग के लिए निर्धारित स्फोरओआरओ में विसंगति दृष्टिगोचर होने के कारण इसमें स्फोरओआरओ का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है । इसी प्रकार नगर के विकसित क्षेत्रों में ग्राम हाउसिंग के लिए न्यूनतम स्फोरओआरओ 1.2 रखा गया है और अविकसित एवं विकासशील क्षेत्रों के लिए 2.5 रखा गया है । नगर

तत्काल क्षेत्रों में मूल्य का उपभोग करने के लिये 'शान्त' क्षेत्रों में विकास क्षेत्रों में जो आउटसिंग विभाग को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं है। यह अनुभव किया गया है कि इन क्षेत्रों में कुछ अवसर पुराने भवनों का पुनर्विकास होकर जो आउटसिंग विभाग की समर्थनार्थ हैं वरन् उन्हे फिर उचित नीति एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

3- कुछ सम्प्रदायों में मुझे यह कानून का निर्देश हुआ है कि भारत द्वारा समस्त विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है कि नगरों की आबादी में आउटसिंग निर्माण के लिए निर्धारित न्यूनतम २००२० आर० १.२ को बढ़ाकर १.५ तथा अधिकतम २.५ को घटाकर १.५ करते हुए पूरे नगर में समान रूप से १.५ एफ०२०आर० निर्धारित किया जाए। मंडायोगना में अन्य भू-उपयोगों में समान प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमत्युक्त जो है कि निर्माण के लिए भी २००२०आर० १.५ अनुमत्युक्त होना ताकि जो आउटसिंग निर्माण को वहाँ एक और समान रूप से प्रोत्साहन मिले वही है। और मंडायोगना में अन्य भू-उपयोगों के लिए निर्धारित २००२०आर० के साथ वित्तगति न हो।

4- उक्त प्राविधान शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा एवं इसके पूर्व के अनुमोदित निर्माण पूर्ण में प्रारम्भ नियम ही प्रभावी होंगे। यह शासनादेश प्रदेश के समस्त सक्रिय प्राविधानों पर लागू होगा। जो आउटसिंग निर्माण के लिए पूर्ण में जारी किए गये शासनादेश संख्या-५३८३/३७-५-८९-२-अ० नी० ०७ दिनांक ०१-०१-९० के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

प्रति,
उप प्रधान मंत्री
प्रमुख मंत्री

संख्या - १११०-आ-३-९६-तदनुमति
प्रतिनिधि निम्न लिखित को प्रेषित :-
१. मुख्य मंत्री, राज्य निर्माण
२. आवास मंत्री, राज्य
३. आवास विभाग के सचिव, अजमेर

आदेश है,
१२-०१-९६
उप प्रधान मंत्री
प्रमुख मंत्री

संख्या 553/9-आ-3-2001 दिनांक 29/8/2002 (आ.व.)

2369

27/11

श्री जे. एस. मिश्र

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

रोवा में

1. आवास आयुक्त,

उ.प्र. आवास एवं नगर विकास

लखनऊ।

2. उपायुक्त,

समस्त विभागात्मक

उत्तर प्रदेश।

आवास आयुक्त-1

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2003

विषय: भूखण्डीय विकास, कोशिकागत नयन की अधिकतम ऊँचाई, तलों की संख्या, रोड-वैक, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. तथा इकाईयों की संख्या के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

भूखण्डीय विकास न नगर नगरपालिका निर्माण के विनियमन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001 दिनांक 29.8.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह सत्य लाया गया है कि उपर शासनादेश के अनुसार "लो-राईज" निर्माण हेतु प्रिबिट नयन तथा नयन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में विद्यमान प्राविधानों के दृष्टिगत नयन को अधिकतम ऊँचाई एवं तलों की संख्या के सम्बन्ध में अतिरिक्त, गुण. हाऊसिंग के नयन का न्यूनतम आवरण 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड एकल भवन की परिधि में आता है। अतः ऐसे भूखण्डों हेतु रोड-वैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त प्रस्तावनों में उचित विनियमों पर समस्त निवासियों का नयन निर्माण एवं विकास उपविधि 2002, शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001 दिनांक 29.8.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह सत्य लाया गया है कि उपर शासनादेश के अनुसार "लो-राईज" निर्माण हेतु प्रिबिट नयन तथा नयन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में विद्यमान प्राविधानों के दृष्टिगत नयन को अधिकतम ऊँचाई एवं तलों की संख्या के सम्बन्ध में अतिरिक्त, गुण. हाऊसिंग के नयन का न्यूनतम आवरण 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड एकल भवन की परिधि में आता है। अतः ऐसे भूखण्डों हेतु रोड-वैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या से सम्बन्धित मानकों का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

2.1 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भवनों की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर (तीन मंजिल) अनुमत्त है जिसका तात्पर्य है कि रिटर्न फ्लोर के अतिरिक्त तीन मंजिल का निर्माण अनुमत्त होगा। स्टिल फ्लोर का प्राविधान न किए जाने की दशा में मंजिलों की अधिकतम संख्या तीन ही अनुमत्त होगी। परन्तु नयन उपविधि, 2000 के प्रसार-3.5.1 में यह प्राविधान है कि 300 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, में भू-आच्छादन के बराबर

1/10/03
20/11/03

अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमति होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई चार मीटर (15 फीट) होगी। इसा संशोधन में शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुपालन में समतल-क्षेत्र स्थित भूखण्डों की "प्राइवरी" तथा "लाइट एण्ड वेन्टीलेशन" की अपेक्षाओं के प्रतिष्ठित उच्च प्रतिक्रिय को विनियानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर अधिक अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हैं, में भू-आवृत्तन के तत्पर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमति होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मीटर) होगी। चार मीटर का तात्पर्य स्टिल्ट-चार तलों से है। अतिरिक्त तल क्षेत्रफल हेतु सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आयोजित विकास शुल्क (आन्तरिक एवं बाह्य) का 50 प्रतिशत प्रचार शुल्क देय होगा। स्टिल्ट फ्लोर के अन्तर्गत किया गया अद्वैत निर्माण शमनीय नहीं होगा तथा स्टिल्ट को पार्किंग के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाए जाने पर विनियानुसार दैधानिक/प्रवर्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उच्च प्रकृति के भवन मानचित्र विकास प्राधिकरण में पूर्व गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति की अध्यक्षता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा आचार एवं विकास परिषद् के प्रकरण में आचार आयुक्त द्वारा की जाएगी।

(2.2) शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 के अनुसार भूखण्डों के विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर (चार मीटर) अनुमति है, जिसका तात्पर्य है कि स्टिल्ट फ्लोर के अतिरिक्त चार मीटर (स्टिल्ट-चार मीटर) का निर्माण अनुमत्त होगा।

2.3 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2009 के अनुसार एकल आवास में 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु सेट-बैक निर्धारित है। शासनादेश संख्या 3001/9-आ-3-2001-19 विविध/2001 दिनांक 29.8.2002 द्वारा ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर कर दिए जाने के फलस्वरूप 1000 से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड भी एकल भवन की परिधि में ला गए हैं, अतः 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए सेट-बैक निम्न तालिकानुसार होगा -

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट-बैक (मीटर)			
	जाने	पीछे	साइड-1	साइड-2
501-1000	6.0	6.0	3.0	1.5
1001-1500	9.9	6.0	4.5	3.0
1501-2000	9.9	6.0	6.0	6.0

ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भवनों हेतु भू-आवृत्तन, एफ.ए.आर. एवं कवरेज की संख्या से सम्बन्धित मानकों को भी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भूके का "आप्टिमम" उपयोग सुनिश्चित हो सके। अतः

87

नगरों की महागोजनाओं में प्रस्तावित अधिकतम जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए गू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं इकाईयों की संख्या निम्न तालिकाानुसार अनुमत्य होंगे-

गूछाण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	गू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	अनुमत्य इकाईयों की संख्या		
			प्रकार सहित	प्रकार सहित	निहित इकाईयों
• 501-750	45	125	5	3	8
• 751-1000	45	120	6	4	10
• 1001-1500	40	120	8	6	14
• 1501-2000	40	120	10	8	18

2.5 गूछण्डीय विकास के अन्तर्गत एकल गूछण्डों (2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल) पर 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवन निर्माण हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 8 मीटर होगी।

2.6 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निहित तथा पूर्व में जारी संगत आदेशों के प्राधिकृत उक्त सीमा तक संबंधित सन्ने जाएंगे।

2.7 उपरोक्त प्राधिकृत उक्त मानदंडों पर भी लागू होंगे जो स्वीकृति हेतु जमा है, परन्तु स्वीकृत नहीं हुए हैं।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

माननीय,

hmv

(जे. एस. मिश्रा)

सचिव

संख्या: 55/3 (1)/2-आ-न-उपविधि/99 (सक) तदुद्दिष्ट।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उप आचार्य एवं विकास परिषद्, सदन-2।
2. अध्यक्ष, संपदा निगम प्राधिकरण, सदन-2।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम निगम-क, सदन-2।
4. प्रमुख निदेशक, उप सड़करी आचार्य एवं डि. स्वयंसेवक।
5. अध्यक्ष, यू.पी.आर्गनोइस एंसाइपलन, सदन-2।
6. अध्यक्ष, यू.पी.रेडन, सदन-2।
7. अन्य निदेशक, नियोजन, आचार्य सदन।

आचार्य

(संलग्न सूचनाएं)

निम्न प्रेषित

प्रेषक,

श्री जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

29

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2002

विषय: भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत गुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित आवासीय योजनाएं सामान्यतः भूखण्डीय विकास (अधिकतम तीन मंजिल भवनों) हेतु अभिकल्पित हैं और उसी के अनुरूप उनमें अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, ड्रेनेज, सीवरज, विद्युत्-आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं, आदि का प्राविधान किया गया है। परन्तु ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत अविवेकपूर्ण ढंग से बढ़ रहे बहुमंजिले निर्माण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप जहाँ एक ओर महायोजना घनत्व का उल्लंघन हो रहा है वहीं दूसरी ओर विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बहुमंजिले निर्माण के कारण अगल-बगल स्थित एकल भवनों की प्राइवसी भंग होती है और प्राकृतिक प्रकाश एवं संग्रातन की व्यवस्था बाधित होती है जिससे रिहायशी पर्यावरण की गुणवत्ता का हास होता है। अतः भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु शासनादेश संख्या एम 155/9-आ-3-2001/19 विविध/2001 दिनांक 26 फरवरी, 2002 द्वारा कतिपय शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए गए थे और यह अपेक्षा की गई थी कि विद्यमान विकसित क्षेत्रों में "लो राईज" एवं "हाई-राईज" क्षेत्रों का चिन्हीकरण छः माह के अन्दर कर लिया जाए तथा उन्हें महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में संशोधन के रूप में शामिल किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों तथा निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश में निहित मंशा के अनुसार "लो राईज" एवं "हाई राईज" क्षेत्रों का चिन्हीकरण व्यवहारिक नहीं है जिसके कारण निजी क्षेत्र में गुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही अवरुद्ध हो गई है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिलिखित शासनादेश को अतिक्रमण करते हुए

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु निम्नलिखित पुनरीक्षित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए जाते हैं :-

2.1 वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर निर्धारित है जो बहुत कम है। इसके कारण भूखण्ड हेतु अनुगम्य भू-आच्छादन के उपरान्त अधिकांश भूमि अग्निशमन सुरक्षा के लिए भवन के चारों ओर वांछित सैट-बैक के अन्तर्गत चली जाती है और भवन में पार्किंग व्यवस्था तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क एवं खुले क्षेत्र का समुचित प्राविधान सम्भव नहीं हो पाता है। अतः ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।

2.2 "निर्मित क्षेत्र" तथा वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भूखण्डों पर अधिकतम 12.5 मीटर ऊँचाई का निर्माण अनुमत्य होगा, 2000 वर्ग मीटर एवं अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई (4 मंजिल तक) के ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों का निर्माण अनुमत्य होगा तथा 4000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के ऐसे भूखण्ड जो 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर देय होगी। परन्तु भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमत्य नहीं होगा। ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति देने से पूर्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं तथा उस क्षेत्र के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत (Integrated) हैं। इस प्रकार वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में देय होगी।

2.3 वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर-2.2 के अनुसार यदि ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमत्य किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा जिससे विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा, अतः ऐसे भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा। परन्तु जिन क्षेत्रों में विद्यमान नीति के अनुसार सुदृढीकरण शुल्क लिया जाए वहाँ पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला निर्माण विकास प्राधिकरण अथवा आवास एवं विकास परिषद की किसी योजना का भाग है और जहाँ विकास शुल्क भूमि के मूल्य में अलग से लिया जा चुका हो, वहाँ पुनः विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि प्रस्तावित स्थल किसी योजना का भाग नहीं है, तो सड़क एवं ड्रेनेज के लिए वर्तमान लागत पर आगणित वाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा।

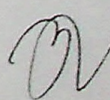
2.4 नए विकसित होने वाले क्षेत्रों में जोनल प्लान/ले-आउट प्लान बनाते समय "लो राईज" एवं "हाई-राईज" क्षेत्र पहले से ही निर्धारित कर लिए जाएं। "लो-राईज" क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर एवं "हाई-राईज" क्षेत्रों में 15 मीटर से अधिक। भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार होगी तथा अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाओं, आदि का अभिकल्पन एवं विकास अनुमत्य एफ.ए.आर. एवं घनत्व के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

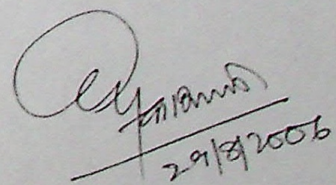
विषय: हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी.पी.आर. के अनुमोदन के संबंध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले विकास क्षेत्र में मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० का चयन शासन द्वारा किया गया है। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इण्डस्ट्रीज लि० को 1765 एकड़ भूमि विकसित करने की अनुमति प्राप्त हुई है एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० को 1784 एकड़ भूमि को विकसित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने धारा-28 के अन्तर्गत सुल्तानपुर रोड पर 4500 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना निर्गत की है। उक्त अधिसूचित भूमि से 1765 एकड़ भूमि परिषद की बैठक में मेसर्स अंसल लि० को हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु दिये जाने का निर्णय लिया है। मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० द्वारा सीतापुर-हरदोई रिंग रोड पर हाईटेक टाउनशिप को विकसित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया था। सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० ने हाईटेक टाउनशिप को विकसित करने हेतु डी.पी.आर. प्रस्तुत की। प्रस्तुत डी.पी.आर. का परीक्षण शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा 13.07.2006 को किया। विकासकर्ता कम्पनी ने सीतापुर-हरदोई रोड पर अपना प्रस्ताव प्रेषित न कर लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर अपना प्रस्ताव प्रेषित किया है। चयनित भूमि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की धारा-28 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि का भाग है एवं विकासकर्ता कम्पनी ने उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से चयनित 1784 एकड़ भूमि को अभी तक अवमुक्त भी नहीं कराया है। सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० ने जो भूमि प्रस्तावित की है उसमें लगभग 400 एकड़ भूमि मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० के पक्ष में अवमुक्त भूमि का भाग है अर्थात् दोनों विकास कर्ता कम्पनियों की भूमि ओवर लैप कर रही है। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० की कान्सेप्चुअल डी.पी.आर. अनुमोदित की जा चुकी है एवं मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० की डी.पी.आर. भूमि की उपलब्धता न होने के फलस्वरूप अनुमोदित नहीं की जा सकी है। इस आशय की सूचना एवं दिनांक: 13.07.2006 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त विकासकर्ता कम्पनी को प्रेषित कर दी गयी है।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि० के पास 1784 एकड़ भूमि की उपलब्धता एवं अर्जन की स्थिति स्पष्ट न होने के फलस्वरूप प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है अस्तु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव शासन को वस्तुस्थिति प्रेषित करते हुए विचारार्थ प्रस्तुत है।

३



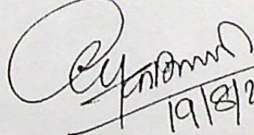

29/8/2006
CTP

विषय: मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या: एसएस-281 तथा एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

प्राधिकरण द्वारा 80 के दशक में ऐशबाग क्षेत्र में मोतीझील के निकट मोतीझील योजना बसायी गयी थी। इस योजना के तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या: एसएस-281 व एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक हेतु 73.46 वर्गमीटर भूमि छोड़ी गयी थीं किन्तु निर्माण करते समय मार्ग डेड एन्ड न रखकर सीधा कर दिया गया, जिसके कारण कल्डीसेक नहीं बनाया गया तथा रिक्त भूमि को दो भूखण्डों में सृजित कर भूखण्ड संख्या: एसएस-282 को आधी भूमि आवंटित कर दी गयी। भूखण्ड संख्या: एसएस-281 के स्वामी द्वारा भी संलग्न भूमि के आवंटन की मांग की गयी है। चूँकि प्रकरण तलपट मानचित्र के भू-उपयोग परिवर्तन का होने के कारण उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के समतुल्य कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक: 06.10.2003 को विषय सं०-6 पर स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी तथा आपत्ति एवं सुझाव उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक: 01.7.2006 को संस्तुति की गयी।

अस्तु गठित समिति तथा स्थल पर डेड एन्ड न बनने के कारण कल्डीसेक के निर्माण न होने की दशा में भू-उपयोग कल्डीसेक के स्थान पर आवासीय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


19/8/2006
मुख्य नगर नियोजक

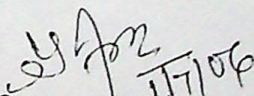
लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड सं०: एसएस-281 एवं एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक (Cul-de-sac) हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक: 6.4.2003 में प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उ०प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के समतुल्य कार्यवाही हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान टाइम्स एवं हिन्दुस्तान) में सूचना दि०: 28.11.2003 को प्रकाशित की गयी। निर्धारित अवधि में कुल दो आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए जो क्रमशः श्री हरि शंकर श्रीवास्तव व श्री राम जनम यादव के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। धारा-13 के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं शासन के आदेश के अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार कर अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना निर्धारित है।

आज दिनांक: 01.7.2006 को प्रातः 12.30 बजे उपरोक्त संदर्भित समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें दोनों आपत्ति कर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमन्त्रित किया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। निम्नलिखित दो आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए, दोनों आपत्ति कर्ताओं के तथ्यों एवं पक्षों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आपत्तिकर्ता भूमि का आवंटन अपने पक्ष में कराना चाहते हैं अर्थात् दोनों आपत्ति/सुझावों का संबंध प्रश्नगत भूमि को कल्डीसेक (यातायात एवं परिवहन) भू-उपयोग से आवासीय किये जाने से संबंधित नहीं है।

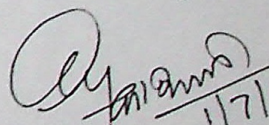
प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन के सभी पहलुओं पर समिति द्वारा विस्तृत एवं सम्यक विचार किया गया तथा यह पाया गया कि

1. प्रश्नगत स्थल की वर्तमान परिस्थितियों में कल्डीसेक के रूप में उपयोगिता शेष नहीं रही है।
2. सामान्यतः कल्डीसेक का प्राविधान मार्ग के अन्त में डेडएन्ड (Dead-end) होने पर किया जाता है परन्तु प्रश्नगत स्थल डेडएन्ड (Dead-end) नहीं है एवं स्थल के ऊपर एवं नीचे सर्कुलेशन एवं टर्निंग हेतु अन्य मार्ग उपलब्ध हैं अतः कल्डीसेक को समाप्त किया जा सकता है।
3. प्रश्नगत कुल 73.46 वर्गमीटर भूमि में से भूखण्ड सं०- एसएस-282 से संलग्न भूमि का आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका है तथा भूखण्ड 281 के साथ संलग्न भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। इस परिस्थिति में भी रिक्त पड़ी भूमि का दुरुपयोग रोकने के लिये स्थल का भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है।

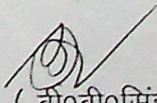
उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के आलोक में प्रश्नगत 73.46 वर्गमीटर भूमि को कल्डीसेक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गई।


(अनिल भटनागर)

प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक


(सी०पी०शर्मा)

मुख्य नगर नियोजक


(बी०बी०सिंह)
उपाध्यक्ष

विषय:- खसरा संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :-

पक्ष श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 15.03.04 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि पक्ष के कथनानुसार 1978 से पंकज सर्विस स्टेशन के नाम चल रहा है। उक्त मानचित्र परीक्षणोपरान्त तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 09.08.04 के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा निर्णय दिया गया था कि "पक्ष द्वारा प्रस्तुत पेट्रोल पम्प के स्थल का भू-उपयोग महायोजना-2001 के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है, जिसमें पेट्रोल पम्प की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है", जोकि पताका-क पर संलग्न है। निस्तीकरण के पश्चात पक्ष ने अपने स्तर से शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया, जिसके क्रम में शासन द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि "पेट्रोल पम्प अगर नियमित है तो उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर कार्यरत पेट्रोल पम्प को कतिपय शर्तों के साथ कार्यरत रहने देने पर प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जा सकती है। उक्त अभिमत के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें" जोकि पताका-ख पर संलग्न है। शासन के पत्र के साथ संलग्न नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के "पत्रांक 4567/व0नि0(4) लखनऊ महा0/2005-06 दिनांक 29.07.05 के अनुसार महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टिका में विशेष अनुमति से प्राधिकरण स्तर से पेट्रोल पम्प अनुमन्य किया जा सकता है" जोकि पताका-ग पर संलग्न है।

अतः आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4910/8-3-05-20एलयूसी/2005 दिनांक 14 दिसम्बर 2005 के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


27/4/2006

(अनूप शर्मा)

प्रभारी प्रवर्तन/भवन-2



(डा0 राम बिलास यादव)

सचिव

विषय : श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री राम कुमार शुक्ला, वेतनमान लिपिक के पद पर विभाग में कार्यरत है। श्री शुक्ला की किडनी का प्रत्यारोपण स्थानीय एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में दिनांक 22.11.96 को किया गया था। वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु श्री शुक्ला की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इनके जीवन रक्षार्थ मानवीय आधार पर चिकित्सा कराने हेतु प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.08.97 तथा दिनांक 22.01.2000 द्वारा क्रमशः रु0-25,000.00 एवं रु0-39,000.00 की धनराशि सहायतार्थ स्वीकृत की गयी थी, जिसके अनुपालन में उक्त धनराशि का भुगतान/समाप्त किया जा चुका है।

श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक पर व्यय की गयी धनराशि रु0-2,00,000.00 के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दिये गये चिकित्सा अग्रिम रु0-25,000.00 + 14,000.00 = रु0-39,000.00 की स्वीकृति के अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय के उपरोक्त आदेश बिन्दु-2 के क्रम में रु0-50,000.00 की चिकित्सा सहायता भविष्य में श्री शुक्ला के जीवन रक्षार्थ दिए जाने की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतः श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन रक्षार्थ रु0-50,000.00 के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

26/11/06

(कै० कै० सिंह)
अवर प्रमारी अधिकारी
(अभिधान)
विकास प्रतिकरण लखनऊ

(डा० राम निलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्रतिकरण

Department of Nephrology & Renal Transplantation
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow - 226 014, INDIA

PGI/Nephro/RK/1506 /06.

Dated : 24.7.06

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. R.K. Shukla, CR NO. 1996012487 is a renal transplant recipient. He has received kidney transplant in this hospital on Nov. 1996. The patient is taking drugs i.e. Wysolone, Azoran, Cyclosporine etc. which are essential & life saving. The approximate expenditure for these medicine would be Rs. 12,000/- per month or Rs. 1,44,000/- per year, from 24.7.06 to 23.7.07.

R. K. Shukla
Signature of patient

Rk
(DR. R.K. SHARMA)

Dr. P. K. SHARMA
PROF. & HEAD
Dept. of Nephrology
S.G.P.G.I.M.S., Lucknow

Prof. R. K. Sharma
MD, DNB (Neph), FAMS,
FASN, FISN, FIMSA
Professor & Head
E-mail: rksharma@sippi.ac.in
Ph. Ext. 2121 (O), 2122 (R)

Prof. Amit Gupta
MD, DNS (Neph),
Professor
E-mail: amitgupta@sippi.ac.in
Ph. Ext. 2123 (O), 2124 (R)

Dr. Sanjeev Gulati
MD, DNB (Paed), FIPN (Toronto)
DNS, DM (Neph)
Associate Professor (Paed Neph)
E-mail: sgulati@sippi.ac.in
Ph. Ext. 2468 (O), 2150 (R)

Dr. Mufazzal Ahmed
MD, DNB, DM (Neph)
Assistant Professor
E-mail: mufazzal@sippi.ac.in
Ph. Ext. 2127 (O), 2128 (R)

Dr. Alok Kumar
MD, DM, DNB (Neph), MNAMS
Assistant Professor
E-mail: alok@sippi.ac.in
Ph. Ext. 2970 (O), 2971 (R)

Dr. Narayan Prasad
MD, DNB (Med), DM, DNB (Neph),
MNAMS
Assistant Professor
E-mail: narayan@sippi.ac.in
Ph. Ext. 3187 (O), 3188 (R)



SANJAY GANDHI POST GRADUATE
INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

RAE BARELI ROAD, LUCKNOW - 226 014

59

Name R K Shukla CR. No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Diagnosis Renal allograft recipient
DOT 22/11/99 pyogenic +

Investigations Ordered

19/8/6

R. tubercular gluteal
abscess ATT since 11-3-06

- ☐ Haematology
- ☐ Coagulation
- ☐ Cl. Chemistry
- ☐ Urinalysis & Fluids
- ☐ Cytology
- ☐ Bacteriology
- ☐ Serology
- ☐ Plain X-ray
- ☐ Ultrasound
- ☐ CT
- ☐ MRI
- ☐ Nuclear Medicine
- ☐ Immunology
- ☐ Medical Genetics
- ☐ Endocrinology
- ☐ GI Endoscopy

Tab Omnacortil 7.5g 1OD

Tab Azoran 7.5g OD HS

Tab Aten 7.5g 1OD

Tab Depin R. 20g 2TID

Tab Pan 40mg 1OD

Tab Combatal 600mg 1OD

Tab P. Side 7.50g 1BD

Next Appointment on at in

Tab Benadone 40g

1/2 OD

Others

- ☐ F.V. after
- ☐ 1 month
- ☐ e
- ☐ reports of

Hb

BUN creat

Iron + TIBC

p-ferritin

f. sat

PSAT

(Signature)

Tab Oflox 200g 1 BD

Tab Aptivate 2TSF BD

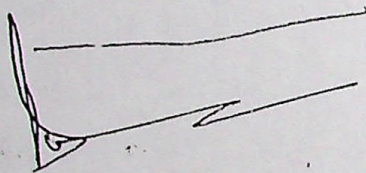
Tab Livogen 1TDS

Tab Folvite 5g 1 QD

Tab INH 300g 1 QD

Inj Eplex. 2000 U S/c

twice weekly



Rb-

पी. के. पैथॉलॉजी

लेब एवं एक्स-रे क्लीनिक

मंजी मौन्टा मार्केट, निकट संजय गांधी संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ फोन
 (0522) 2668047, 2668226 E-mail : drpk@pkpathology.com Website : www.pkpathology.com



Dr. P. K. Gupta

B.Sc., M.B.B.S., M.D. (Path.)

FORMERLY PATHOLOGIST

King George Medical College Lucknow

MEMBER OF IAPM

International Academy of Pathology

OUR MOTTO - PATIENT CARE, ACCURACY, SPEED & ETHICAL STANDARD

Name : R.K. SHUKLA

Lab.No. : 49

Date : 19/08/2006

Sex : Male

Specimen : BLOOD

Haemoglobin : 7.5 gm %

Total Leucocyte Count : 6,200 /cmm

Blood Urea Nitrogen : 29.0 mg%
 (Normal Range : 10 - 20 mg%)

Serum Creatinine : 2.55 mg%
 (Normal Range : 0.5 - 1.5 mg%)

S.G.P.T : 24.0 U/L
 (Normal Range : 6 - 40 U/L)

S.G.O.T : 31.0 U/L
 (Normal Range : 6 - 40 U/L)

Dr. P. K. GUPTA
 MBBS, MD, Path



N.B. - If there is Disparity with clinical setting, Please contact immediately to Lab.
 Equipped with Computersied Autoanalyser, Microwell Elisa Reader, Fully Automatic Digital Hematology
 Cell Counter ION Selective Electrodes Based Electrolyte Analyser, E.C.G. & X-Ray Unit (Siemen's)

Title : 8:00 A.M. to 8:00 P.M. Sunday 10:30 A.M. to 1:00 P.M.

शीघ्र रॉच एवं एक्सरे की सुविधा उपलब्ध

प्रदेश की प्रथम भूजल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना को (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) लखनऊ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्ताव को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्राम किला मोहम्मदी, सालेह नगर, भदरूख, बंगला बाजार आदि गावों के मध्य आदिकाल से अहल नामक झील स्थित थी। नगरीय विकास की धारा में यह झील पूरी तरह से सिल्ट और कचरे से भर गयी। वर्ष 1995 में प्राधिकरण ने कानपुर रोड योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में स्मृति उपवन नामक एक परियोजना प्रारम्भ की थी, परन्तु इस परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में जो वनीकरण किया गया था उसके अंतर्गत 13 एकड़ क्षेत्र में ही वन संरक्षित रखा जा सका। शेष झील का 21 एकड़ क्षेत्र लो-लाईग क्षेत्र के रूप में रह गया। इस क्षेत्र का वर्षा जल इसी झील में एकत्र होता एवं 25 वर्ष पूर्व तक इस क्षेत्र में जलभराव की कोई समस्या नहीं थी। झील के समाप्त होने तथा शहरी विकास के कारण इस क्षेत्र में जलभराव की भी समस्या विकराल रूप धारण करने लगी।

प्राधिकरण ने इस समस्या का अध्ययन कर इस क्षेत्र को प्रदेश की प्रथम भूजल सर्वेक्षण एवं प्राचीन झील संरक्षण की एक योजना परिकल्पित की।

इस योजना के अंतर्गत 8.0 एवं 13.0 एकड़ क्षेत्र की दो झीलों की डिसिल्टिंग की जानी है तथा पूरे 101 एकड़ क्षेत्र एवं इसके समीप की सड़कों का वर्षाजल इन झीलों में लाया जायेगा। इस क्षेत्र में इस कार्य हेतु कोई मिट्टी भराई नहीं की जायेगी। मात्र फुटपाथ पर मिट्टी भराई का कार्य किया जायेगा।

इस क्षेत्र में पूर्व से 54 प्रकार के 3500 वृक्ष लगे हैं तथा 5000 और वृक्ष 47 प्रजातियों के लगाये जायेंगे। इस प्रकार से इस नगरीय उपवन में 101 भारतीय विदेशी प्रजातियां लगाई जायेगी।

इस उपवन में नगरीय वन के अतिरिक्त जलक्रीड़ा, बर्ड वाचिंग पैवेलियन, आधुनिक सुविधाओं-युक्त  कॉटेजेज जिसमें नाव से भी आया-जाया जा सकेगा, की सुविधा के साथ भोजनालय, आधुनिक व्यायामशाला, प्रशासनिक भवन, आदि का प्राविधान प्रस्तावित है।

इस योजना के क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	क्षेत्रफल का विवरण	क्षेत्रफल
1	कुल क्षेत्रफल	101 एकड़
2	संरक्षण की जाने वाली झील का क्षेत्रफल	21 एकड़
3	पूर्व विकसित वन का क्षेत्रफल	13 एकड़
4	विकसित किये जाने वाले वन का क्षेत्रफल	62.5 एकड़
5	विशेष बगीचों का क्षेत्रफल	4.50 एकड़
6	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल	2.65 एकड़

इस परियोजना की लागत रु0 15.00 करोड़ के आसपास आंकी गई है। परियोजना की डिजाइन प्रमुख लैण्डस्केप आर्किटेक्ट प्रोफेसर शहीर द्वारा तैयार की जा रही है। परियोजना की कन्सेप्ट ड्राइंग तैयार कर दी गई है। 15 अगस्त 2006 को माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा योजना का शिलान्यास किया जा चुका है।

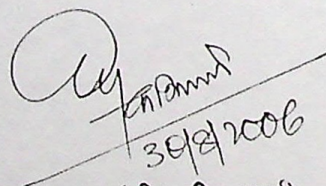
उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

23/8/06
२

विषय: ह्यूमन एण्ड एजुकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

ह्यूमन एण्ड एजुकेशनल रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर को 7067.61 वर्गमीटर भूमि इण्टरमीडिएट स्कूल के लिये आवंटित की गयी थी। तलपट मानचित्र में नर्सरी/प्राइमरी स्कूल के लिये प्रस्तावित है। बल्कसेल की पत्रावली पर तत्कालीन सचिव महोदय की संस्तुति पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त भूखण्ड इण्टरमीडिएट के लिये आवंटित किये जाने हेतु अनापत्ति दी है एवं लीज डीड भी इण्टरमीडिएट कालेज के लिये निष्पादित की गयी है। भूखण्ड की कारस्टिंग इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज के मानक के अनुसार करते हुए, सम्पूर्ण वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी। पक्ष द्वारा मानचित्र अनुमोदन हेतु प्राधिकरण में उपलब्ध कराया गया है वह इण्टरमीडिएट कालेज के मानकों के अनुसार था। किन्तु तलपट मानचित्र में प्राइमरी स्कूल अंकित होने के कारण, अनुमोदन प्राइमरी स्कूल के लिये किया गया है। सोसायटी के सचिव द्वारा एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया है कि प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने हेतु मानचित्र में तत्सीमा तक संशोधित कर दिया जाये। बल्कसेल की आख्या में अनुसचिव द्वारा भी संस्तुति की गयी है। चूँकि प्रकरण तलपट मानचित्र में परिवर्तन का है, अतः शासनादेश संख्या: 2438/9-आ-3-90-60एलयूसी/96 दिनांक: 13 अक्टूबर, 1998 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के समतुल्य कार्यवाही कर प्राइमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।


30/8/2006
(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर मिश्रजक

संख्या-2438/9-आ-3-90-60एल.यू.सी./96

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 1998

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 4900/9-आ-3-96-60एल.यू.सी./96 दिनांक: 26.12.96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निर्देश दिये गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिये भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत करने व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर । अतः ले-आउट प्लान में संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुर्नविचार किया गया।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये गये विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् को योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के स्तर पर ही सम्पादित की जाये परन्तु ऐसे संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाये। अर्थात् ऐसे मामलों में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तथा आपत्ति कर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते

हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिये भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 26.12.96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

ह०/—
(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या-2438(1)/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपिक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग
3. गार्ड फाइल।
4. उ०प्र० आवास बन्धु।

आज्ञा से,
ह०/—
(एच०पी०सिंह)
अनुसचिव

विषय: प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव: सुरभि पब्लिक स्कूल को 3131.34 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी में वर्ष 2000 में आवंटित किया गया था। प्रबन्धक सुरभि पब्लिक स्कूल ने दिनांक: 02.11.2001 को प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया कि प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी में एक अन्य भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर है, को उपरोक्त आवंटित भूखण्ड के स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाये जिसमें इण्टरमीडिएट स्तर का स्कूल खोला जा सके। प्रार्थी के अनुरोध पर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक: 17.05.2003 एवं 22.01.2004 में प्रस्ताव भूखण्ड के परिवर्तन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रस्तावित भूखण्ड का भू-उपयोग पार्क, प्ले ग्राउण्ड एण्ड ओपेन स्पेस, ग्रुप हाउसिंग अंकित किया गया। दिनांक: 17.05.03 की बैठक में प्रस्ताव को निरस्त किया गया जबकि 22.10.2004 की बैठक में उपाध्यक्ष महोदय को स्थल निरीक्षण कर अपना अभिमत देने हेतु अधिकृत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय ने एक उपसमिति का गठन किया जिसमें मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० एवं प्रभारी बल्कसेल को नामित किया। समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग कम्युनिटी फ़ैसिलिटी ही है। कम्युनिटी फ़ैसिलिटी में जोनिंग प्राविधानों के अन्तर्गत स्कूल को अनुमन्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के आधार पर पुनः प्रस्ताव दिनांक: 09.07.2005 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रेषित किया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

श्री जनेश्वर मिश्र, सांसद सदस्य (राज्य सभा) एवं श्री जय शंकर पाण्डेय, पूर्व विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं श्री वैज नाथ, विधायक समाजवादी पार्टी ने सुरभि पब्लिक स्कूल के लिये प्रस्तावित भूखण्ड को आवंटित करने के लिये पुनः विचार करने के लिये अनुरोध किया है। मा० सांसद एवं विधायक गणों के अनुरोध पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनः प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावित भूखण्ड पर अब तक हुई कार्यवाही एवं बोर्ड के निर्णय का तथ्यात्मक विवरण संलग्न करते हुए 3131.34 वर्गमीटर के आवंटित भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड में परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

जनेश्वर मिश्र

संस. सदस्य
(राज्य सभा)

VIP [R206] 080



8, हा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली 110001,
फ़ोन 23351180/23722112.

68

संख्या CM 385/माठ-1-2006

तारीख 10, अप्रैल 2006

मुख्य मंत्री, कार्यालय

संसद कक्षा

प्रिय भाई मुलायम सिंह जी, संख्या सी.एम.०/एम.पी.०/... 285675/2006

दिनांक... 10.4.2006

प्रबन्धक/तहसिल, सुरभी पब्लिक कालेज, केशवनगर, सीतापुर, रोड़, लखनऊ, उ.प्र. के संलग्न आवेदन का अवलोकन करें। इन्होंने अपने स्वतः वर्णित आवेदन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शनी योजना के ले आऊट में हाईस्कूल/इण्टर कालेज को भूखण्ड का प्रावधान शामिल कर उसे सुरभी पब्लिक स्कूल के पक्ष में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया है।

कृपया गामीण अंचल के छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु सुरभी पब्लिक स्कूल के पक्ष में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश निर्गत करने का कष्ट

सादर,

आपका,

(जनेश्वर मिश्र)

श्री मुलायम सिंह यादव,
संसद कक्षा, विधानसभा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उ0प्र0।

सचिव, आवास
कृपया आख्या सहित पत्रावली
प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

27-04-2006
(जनता प्रसाद)
प्रिंसिपल, मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश

संसद सदस्य
(राज्य सभा)11
12

दिनांक-11.7.2006

प्रिय भाई मुलायम सिंह जी,

श्री जयशंकर पाण्डेय, पूर्व विधायक, फैजाबाद, उ०प्र० के संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन करें। जिसमें उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी, सेक्टर-बी, लखनऊ में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल, लखनऊ को आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है।

कृपया आप इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

सप्रेम,

भवदीय

(जनेश्वर मिश्र)

श्री मुलायम सिंह यादव,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

जयशंकर पाण्डेय

पूर्व विधायक, अयोध्या
पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
फैजाबाद



निवास:-

149, अंगूरीबाग कालोनी, फैजाबाद
दूरभाष (निवास) 05278-261312
मोबाईल 9415139661

70

पत्रांक

दिनांक ..11.7.06..

सेवा में,

माननीय श्री जनेश्वर मिश्र जी,
सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
समाजवादी पार्टी।

विषय:- सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित करने हेतु।

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन यह है कि सीतापुर रोड, प्रियदर्शनी कालोनी सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड 3131.34 वर्गमीटर को बदलकर सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्गमीटर भूखण्ड सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित करने हेतु आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र संख्या-वी0आई0पी0/आर0/06/080 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को लिखा था जिस पर प्रमुख सचिव आवास महोदय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय से पत्रावली अवलोकन करने हेतु मंगा लिया है। कुछ कतिपय अधिकारियों की द्वेष भावना के कारण अभी तक भूमि आवंटित नहीं हो सकी है।

कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उपरोक्त विषयक भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित कराने की कृपा करें।

मैं आपका आभारी रहूंगा।

आदर सहित,

भवदीय

जयशंकर पाण्डेय
पूर्व विधायक-फैजाबाद

तथ दूवे

विधायक

कटरा बाजार, गोण्डा।



आवास

- 1. खेल रोड, गोण्डा। (C) 2260
- 2. ग्राम 0 पौठ परगा महेशी (C) 276537
- 3. C 3 दारुलशाफा लखनऊ (C) 2220223

मो : 9415120762

दिनांक 16.09.2004

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

कृपया अनुरोधानुसार कार्यवाही किये जाने के निदेश दिये गये हैं।

१६-०९-२००४ (मोहताम हुसैन)

सचिव, मुद्रा मंत्री

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश राज्य में आवंटित स्कूल भूखण्ड (3131 वर्गमी०)

विषय - सुरभि पब्लिक स्कूल, लखनऊ को सीतापुर रोड त्रिपदरनी योजना के सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड (6331 वर्ग मीटर) में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

मुद्रा मंत्री कार्यालय

दिनांक 16/09/2004

109697/04

14/09/04

उपरोक्त विषयक प्रत्येक सुरभि पब्लिक स्कूल के लिये स्पष्ट पत्र में अंकित प्रकरण के सम्बन्ध में मैं आपको सामुदायिक चर्चा प्रेषित करना चाहता हूँ -

1. सुरभि पब्लिक स्कूल को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15-9-2000 को एक स्कूल भूखण्ड (3131 वर्ग मी०) आवंटित किया गया। इसके इण्टरमीडिएट कालेज हेतु उपयुक्त न होने के कारण कालेज के प्रबंधक द्वारा दिनांक 2-11-2001 को उरी रोक्टर में उपलब्ध सुविधाओं हेतु आरक्षित एक बड़े भूखण्ड (6331 वर्ग मी०) से परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया।
2. महायोजना एवं नवीन भवन विकास उपविधि के माफकों के अनुसार जोस उपरान्त तत्कालीन मुख्य नगर नियोजक द्वारा सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड को विद्यालय के पक्ष में परिवर्तित करने की संस्तुति प्रेषित की गयी। जिस पर दिनांक 19-07-2002 को सचिव प्राधिकरण द्वारा ले आउट में फोरमिडिटी लेण्ड को स्कूल तथा भूखण्ड को फोरमिडिटी मार्क करने की संस्तुति पर उपाध्यक्ष द्वारा ऐसा ही किया जाने का आदेश दिये गये।
3. तदोपरान्त दिनांक 30-10-2002 को मानविकी की स्वीकृति / प्रमाण हेतु गठित नियोजन समिति की बैठक में भी परिवर्तन पर अपनी सौहार्दिक सहमति प्रदान की तथा समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बैठक में उक्त निर्णय के समक्ष प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक श्री जी० एस० गंगूल (अब निवृत्त) तथा उपनगरनियोजक श्री रवि जी० भी उपस्थित थे।
4. लालचवश नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड को भूा हाउसिंग हेतु आरक्षित कताकर प्राधिकरण बोर्ड की मत दो बैठक में एक सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत करते रहे। जिस कारण वह बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया।
5. भूरे द्वारा उपाध्यक्ष ल० वि० प्र० को प्रेषित एक पत्र के सहित दिनांक 2-5-2004 को इस प्रकरण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई। जिसमें नियोजन विभाग द्वारा उपरोक्त बिन्दु-४ पर अंकित अपनी भी को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत भूखण्ड को सुविधाओं हेतु आरक्षित हो मान लिया।

चूंकि स्कूल भू-उपयोग भी सुविधाओं का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई भू-उपयोग परिवर्तन निहित नहीं है, बल्कि सुविधाओं के अन्तर्गत ही स्कूल भूखण्ड का ले-आउट में मात्र रैखांकन कर कार्यवाही किया जाना है। अतः उपर्युक्त क्रम में निवेदन है कि प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 22.01.2004 की बैठक के निर्णय संलग्नक -17) के अनुसार उपाध्यक्ष, ल० वि० प्र० को प्रस्तुत भूखण्ड को सुरभि पब्लिक स्कूल के पक्ष में यथाशीघ्र परिवर्तित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

C. J. P.

श्री रेणु सिंह सावर

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

24/04

E, S

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विभिन्न खंड, गोगली नगर, लखनऊ। संख्या 104/प्र.अ.वि.ल.क./BS दिनांक 11/7/04	सेवा में, अनु. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ।
---	--

विषय

सुरंगि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या सीएम-519/9-आ-1-03 जम्हडीप/04 दिनांक 23 जनवरी, 2004 एवं पत्र संख्या-सीएम-152/9-आ-1-2004-37 एलडीप/01 दिनांक 7 अप्रैल, 2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत संस्था को प्रियदर्शिनी योजना के अन्तर्गत लगभग 31.31 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड आवंटित किया गया था किन्तु संस्था के अनुरोध पर विभाग द्वारा एक अन्य भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 6330 वर्गमीटर है, को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग गुप-हाउसिंग होने के दृष्टिगत पूर्व में यशवि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था किन्तु संस्था के अनुरोध पर एवं आयुक्त महोदय के निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 22.1.2004 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण कर प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्पश्चात उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश न प्रभारी अधिकारी-बन्क रोड, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 27.5.2004 को एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकट हुआ कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलेपट मानचित्र सम्पूर्ण रोडवर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिए अनुमोदित कराया

गया है तथा वह भूखण्ड जिसे मानचित्र में गुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आउट का भाग नहीं है। उक्त बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूतल प्रश्नगत भूखण्ड को गुप हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ऐसी स्थिति में गुप हाऊसिंग नहीं जाना जा सकता है, वरन् इसे 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 में लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

उपर्युक्त क्रम में प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन सुविधाओं हेतु एवं जनसुविधाओं हेतु आपेक्षित क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को आगामी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

भवदीय,

[Signature]

(एसओडीओ दोहर)

अपर सचिव

प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 के विषय संख्या-13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, तखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. श्री जी०एस० गोयल, मुख्य नगर नियोजक, तखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री एस०एम० दत्तल, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
3. श्री एस०बी० भटनागर, एजीक्यूटिव सिस्टम/प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, तखनऊ विकास प्राधिकरण।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में लिए गये निर्णय के कम में उपाध्यक्ष, तखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया। आज की बैठक में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में वर्ष 1995 में अनुमोदित प्रश्नगत सेक्टर के तलपट मानचित्र के की-प्लान का अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिये ही अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे इस ले-आउट में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आउट का भाग नहीं है। इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में अन्य कोई मानचित्र भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पुष्टि हो सके कि प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग भू-उपयोग में नियमानुसार परिवर्तन किया गया है। अतः मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप-हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ग्रुप हाऊसिंग नहीं माना जा सकता है, वरन् इसे वर्ष 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जायेगा। उपर्युक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्ध के हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 में लिये गये निर्णय के कम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(एस०बी० भटनागर)
एजीक्यूटिव सिस्टम/
प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल
त० वि० प्रा०।

(एस०एम० दत्तल)
नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उत्तर प्रदेश।

(जी०एस० गोयल)
मुख्य नगर नियोजक,
त० वि० प्रा०।

(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष,
तखनऊ विकास प्राधिकरण,

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

पत्र संख्या:- 336/सीटीपी/2005

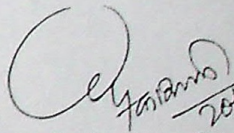
दिनांक 20 दिसम्बर, 2005

सहायक जनसूचना अधिकारी,

जनसूचना अनुभाग से संबंधित अपने पत्र संख्या: 27/ज0सू0का0/05, दि०: 08.11.2005 (फार्म सं०-59) का सन्दर्भ लें जिसके कम में प्रबन्धक/सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल, स्थित केशवनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ (निकट प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर-बी) द्वारा वांछित उनके प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड की निम्नलिखित बैठकों में रखे गये प्रस्ताव एवं उन पर लिये गये निर्णय की छाया प्रतियाँ पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं :-

1. दिनांक: 17.05.2003 — विषय सं०-10
2. दिनांक: 22.01.2004 — विषय सं०-13
3. दिनांक: 15.07.2004 — विषय सं०-11
4. दिनांक: 18.11.2004 — विषय सं०-13
5. दिनांक: 19.03.2005 — विषय सं०-27
6. दिनांक: 09.07.2005 — विषय सं०-13

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (13 पृष्ठ)।


(सी०पी०शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

प्रतिलिपि:

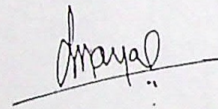
जनसूचना अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी०पी०शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, तीतापुर रोड के सेक्टर-बी में
तुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड
को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार
=====

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17.5.2003 में उपरोक्त विषयक
प्रस्ताव संख्या-10 प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था।
प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को अमान्य पाते
हुए इसे निरस्त कर दिया गया था। पूर्व बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव एवम्
प्राधिकरण के निर्णय की प्रति संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। इस
सम्बन्ध में श्री देवी दयाल शास्त्री, सदस्य विधान परिषद द्वारा अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को दिनांक -
31.7.2003 को प्रेषित पत्र में प्रसंगगत प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण
को आगामी बैठक में पुनः सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है,
जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के
निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र संलग्नक-2 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है। उक्त
के क्रम में प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

0-0-0



निर्णय : डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक तथा गाँधी सेतु के निर्माण के पश्चात वैराज से लेकर सहारा शहर के बीच के स्थल का विकास वहाँ की स्थानीय आवश्यकता बन गई थी। इसको देखते हुए समाबाई अम्बेडकर पर्यटक स्थल के कराये गये विभिन्न विकास कार्यों से प्राधिकरण अवगत हुए तथा अब तक कराये गये कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिये गये कि इस परियोजना में जो भी व्यय अब तक हुए है उसकी प्रतिपूर्ति शासन से शीघ्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : ७ वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : ८/१५८ से ८/१६० के सम्मुख स्थित पार्क में श्री चन्द्रदीप सिंह के निर्मित भवन की भूमि के भू-उपयोग को 'पार्क' से 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव रथगित किया गया।

विषय संख्या : ८ भूखण्ड संख्या : १/७ वारुण खण्ड के आवन्ती श्री सत्य देव पचीरी के प्रार्थनापत्र में अंकित लोकेशन शुल्क को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : ९ भगवान इन्डरटीज की पट्टागत भूमि संख्या: ७२ ए, ७३ के ग्राम-करहेटा, ऐशवाग इन्डरटियल एरिया के फी-होल्ड के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

✓ विषय संख्या : १० प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्ति ३१३१.३४ वर्ग मी० स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अमान्य पाया गया तथा निरस्त किया गया।

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर- बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आबंटित 3131.34 वर्गमी० ^{स्कूल भूखण्ड} को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल अनुभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल हेतु एक भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी० आबंटित किया गया था।

कालान्तर में सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उक्त स्कूल भूखण्ड के स्थान पर इन्हें इस योजना में जन सुविधाओं हेतु आरक्षित 6331.65 वर्ग मी० की भूमि आबंटित कर दी जाये, जिससे वह इस स्थल पर इण्टरमीडिएट स्तर तक का विद्यालय चला सके।

इस सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग में परीक्षण कराया गया तथा यह अवगत कराया कि नियोजन की दृष्टि से जनसुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड का सुरभि पब्लिक स्कूल को आबंटित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु उचित होगा कि उक्त स्कूल को आबंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी० को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। उक्त परीक्षण में यह उल्लेख किया गया कि 6331.65 वर्ग मी० क्षेत्रफल नियोजन के माप दण्डों के अनुसार इण्टरमीडिएट कालेज हेतु कम है।

उपर्युक्त क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा जन सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि को स्कूल हेतु तथा स्कूल हेतु आरक्षित भूमि को जन सुविधाओं मार्क करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के क्रम में स्थल पर नापजोख के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत सेक्टर [पार्ट] का भू उपयोग लखनऊ नगर की महायोजना में 'पार्क एवं क्रीडास्थल' के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जबकि स्थल पर पूर्व में ही प्राधिकरण की योजना विकसित हो गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को प्राधिकरण की योजनाओं में तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के समक्ष दि० 30.10.02 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीतापुर रोड प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर बी की वह भूमि जिसे भूलवश लखनऊ महायोजना में पार्क एवं क्रीडा स्थल दर्शा दिया गया है, के भूउपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा लखनऊ की आगामी महायोजना के ड्राफ्ट में प्रश्नगत भूमि के भूउपयोग को आवासीय में रखने हेतु कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर बी में प्रस्तावित प्रश्नगत स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मी० के भू उपयोग को जनसुविधाओं हेतु तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमी० के भूउपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव समस्त तथ्यों के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उपसमिति की बैठक का कार्यवृत्त अनुसूची 1 पर संलग्न है।

कालान्तर में नियोजन अनुभाग के अभिलेखों में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक

अन्य अनुमोदित लेआउट प्लान भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें प्रश्नगत सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित दर्शाया गया। यह लेआउट प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमिति के स्तर से भी अनुमोदित है।

उक्त के दृष्टिगत स्कूल भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखण्ड से परिवर्तित करना सम्भव नहीं हो सका, किन्तु सुरभि पब्लिक स्कूल प्रबन्धक द्वारा बार बार स्कूल भूखण्ड को इसी भूखण्ड से परिवर्तित कि-येजाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में निम्न विकल्प विचारणीय हैं:

1. सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत रखा जाये।
2. यदि ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखण्ड से स्कूल भूखण्ड परिवर्तित कि-या जाता है तो ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर का क्षेत्रफल अन्य सुविधाओं से ग्रुप हाउसिंग हेतु परिवर्तित किया जाये।
3. लेआउट में भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्यवाही नियमानुसार करायी जाये।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Amayal
21/5/03

Amayal
71

128
 लॉन्विप्रां की बैठक 22.01.2004

विषय संख्या : 12 कपूरथला, अलीगंज स्थित कागर्सिखल कागपहोवरा के प्लान नं: 1,2, एवं 7 पर निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग एवं विधि विभाग वंज मंतव्य प्रस्ताव पर प्राप्त करने के उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

✓ विषय संख्या : 13

प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, लॉन्विप्रां को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 14

त्रुटनन्द बालचंद एजुकेशन फाउन्डेशन को भूमि आवंटन विषयक।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15

डिवाइन हार्ट फाउन्डेशन (इण्डिया) को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड (संस्थागत) में भूमि आवंटन विषयक।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि स्थायी विभाग से निर्मित हॉस्पिटल के मानकों की पूर्ति करते हों। तब अनुमोदन-प्रदान-किया-जाता-है।

विषय संख्या : 16

अवंष अपार्टमेंट में रिक्त फ्लैट्स के मूल्य में 50 प्रतिशत पर कट्टा देने तथा 50 प्रतिशत को किश्तों में लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार व्यापक प्रचार प्रसार करके इस सम्पत्ति को विक्रय का प्रयास किया जाये। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत आवंटन के पश्चात् जमा करना होगा तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एक वर्ष के अन्दर 25-25 प्रतिशत की दो किश्तों में देय होगी।

नगरपालिका विकास कार्यको लागि बोर्ड को बैठक
 दिनांक 15 जुलाई 2004 को कार्यसूचीबाट

(3)a

81

विषय संख्या : 11

5

प्राधिकरण को विषयदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर नगर म
 सुरंगि पब्लिक स्कूल को आसन्नित 2777 अ वर्गमीटर भूमि को
 परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया इसका पूरा
 आसन्नित भूखण्ड को ही यथावत् रखा जाये

अनुपूरक

विषय संख्या : 1

हरीनाथ क्षेत्र म प्रस्तावित "अन्धता भवन" के निर्माण स्थल के
 भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन पदान किया गया
 भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु प्रकरण शरान को
 अग्रसारित किया जाये

अनुपूरक

विषय संख्या : 2

जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एफ" म भूखण्ड
 संख्या:सी-2/7609 के समुख तलापट मानचित्र म अक्किन पाइमरी
 स्कूल की भूमि के उपयोग को पार्क म परिवर्तित किये जाने के
 सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन पदान किया गया

अनुपूरक

विषय संख्या : 3

महयोजना 2007-2027 तैयार किये जाने हेतु यू०डी०पी०एफ०आई०
 गाइड लाइन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

विचारोपरान्त समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर सहमति व्यक्त की
 गई तथा निर्देशित किया गया कि तत्काल महयोजना के पारम
 को अन्तिम रूप देने हुए अगस्त, 2008 के पथम संस्कार म
 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये

Chandra

2

17

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार

प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी योजना सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवंटित 3131.34 वर्ग मीटर स्कूल भूखण्ड को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.1.2004 में विषय संख्या-13(संलग्नक-1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण को निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया। प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.2.2004 को स्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्पश्चात उनके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश व प्रभारी अधिकारी-बल्क सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 27.5.2004 को एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1995 में अनुमोदित तलपट मानचित्र सम्पूर्ण सेक्टर का न होकर केवल पार्ट भाग के लिए अनुमोदित कराया गया है तथा वह भूखण्ड जिसे मानचित्र में ग्रुप हाऊसिंग हेतु दर्शाया गया है वह इस अनुमोदित ले-आउट का भाग नहीं है। उक्त बैठक में यह मत स्थिर हुआ कि सम्भवतः तत्समय ड्राफ्टिंग त्रुटि के कारण भूलवश प्रश्नगत भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग हेतु अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग ऐसी स्थिति में ग्रुप हाऊसिंग नहीं जाना जा सकता है, वरन् इस 1995 से पूर्व के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र के अनुसार सुविधाओं हेतु ही माना जाएगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्र की स्वीकृति/संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में हुई बैठक दिनांक 30.10.2002 (कार्यवृत्त-संलग्नक-2) में लिये गये निर्णय के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.5.2004 में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।

उपर्युक्त क्रम में प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन सुविधाओं हेतु एवं जनसुविधाओं हेतु आपेक्षित क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को स्कूल में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

0-0-0-0

Amrta

18/01/2004

:: ७ ::

अनु०वि०संख्या : १२ गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-३ में भूखण्ड संख्या : ३/४७ के सामने ले-आउट में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड (क्षेत्रफल १००२.०३ वर्गमी०) के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

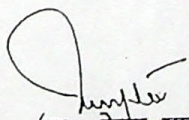
निर्णय : गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड-३ में भूखण्ड संख्या : ३/४७ के सामने ले-आउट में स्कूल हेतु आरक्षित भूखण्ड(क्षे.फ. १००२.०३ वर्ग मी.) का भू-उपयोग स्कूल से परिवर्तित कर आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-१३ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

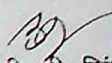
अनु०वि०संख्या: १४ स्वै०शमन योजना-६८ के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की शमन उपसमिति द्वारा निरस्त किये गये प्रकरणों पर शासन द्वारा गठित पुनरीक्षण समिति के समक्ष रखे गये प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० की प्रकरण के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

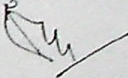
उपरोक्त के अतिरिक्त मूल कार्य-सूची में सम्मिलित विषय संख्या: ५ से १६ तक एवं अनुपूरक कार्यसूची के विषय संख्या: १३ को समयाभाव के कारण स्थगित किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव


(वी०वी०सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(डी०सी०लाखा)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अनुसूचक

विषय संख्या:- 13

पृष्ठ संख्या:- 106

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

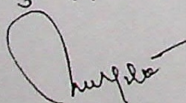
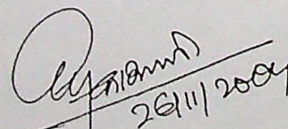
सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या-10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध में आवंटन के नियम, शर्त एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप-दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन-सुविधाओं हेतु एवं जन-सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

19 मई 2015

(5) a

85

विषय संख्या : 26

गो0न0योजना के विकल्प खण्ड में विशेष सुरक्षा बेल परिसर के निर्माण हेतु रु. 363.41 लाख अग्रिम भुगतान प्राधिकरण निधि से किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

✓ विषय संख्या : 27

सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर बी में आवन्तित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्गमीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्गमीटर को आवन्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 28

मोटर साइकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 29

सोसायटी फार अवेयरनेस आफ न्युरल डिजीजेस को गोमती नगर विस्तार में भूमि आवनटन विषयक।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. को अधिकृत किया गया कि वे टर्मडआफ रेफरेन्स निर्धारित कर लें तथा सन्तुष्टि कर लें कि संस्था वास्तव में धर्मार्थ संस्था है, लाभ-हानि के बिना कार्य करेगी। संस्था के संविधान का समुचित अध्ययन कर लिया जाये।

(कु० रेखा गुप्ता)
सचिव

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डी०सी०लाखा)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(डी०सी०लाखा)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

106

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या-10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड गुप्त हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध में आवंटन के नियम, शर्तें एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप-दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन-सुविधाओं हेतु एवं जन-सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

CTP
26/11/2004

[Signature]

[Signature]
26/11/2004

श्री रजा
अध्यक्ष आधिकारी

विषय संख्या: 12

भूखण्ड संख्या-13 राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक-में बेसमेंट का सम्पूर्ण भाग, भूतल का आंशिक भाग तथा छठे तल का लगभग 85 प्रतिशत भाग का वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायिक उपयोग की मास्टर प्लान-2001 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के कम में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया ।

✓ विषय संख्या: 13

सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग. मी. के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग.मी. को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया ।

विषय संख्या: 14

मोटर साइकिल/स्कूटर/कार हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मोटरसाइकिल/स्कूटर हेतु रु0500/- एवं कार हेतु रु0 800/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या: 15

विकास प्राधिकरण लखनऊ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त अधिसंख्या पदों के सृजन/स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जाये ।

विषय संख्या: 16

गोमती तट विकास परियोजना के अन्तर्गत कुड़ियाघाट क्षेत्र में पक्का पुल से कला कोठी तक तट विकास एवं सौन्दर्यीकरण ।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया ।

✓

✓

विषय : सुरभि पब्लिक स्कूल को प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के सेक्टर-बी में आवंटित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के स्थान पर सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

सुरभि पब्लिक स्कूल को बल्कसेल विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड के अन्तर्गत स्कूल भूखण्ड हेतु एक भूखण्ड 3131.34 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। सचिव, सुरभि पब्लिक स्कूल द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसी सेक्टर में आवंटित भूखण्ड के समीप ही एक अन्य भूखण्ड, जो जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित है, इसका क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर है, आवंटित कर दिया जाये क्योंकि स्कूल के लिये प्ले फील्ड की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्नगत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2003 में विषय संख्या-10 के अन्तर्गत रखा गया था जिसमें इन्टरमीडिएट कालेज के लिए भूखण्ड नियोजन मानकों के अनुसार कम होने, महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" होने तथा नियोजन विभाग में वर्ष 1995 में प्रश्नगत सेक्टर का एक अन्य अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड गुप हाउसिंग हेतु आरक्षित होने के कारण सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया एवं निर्णय लिया गया कि सुरभि पब्लिक स्कूल को पूर्व आवंटित स्थल पर ही यथावत् रखा जाये।

सुरभि पब्लिक स्कूल के सचिव द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.01.2004 में विषय संख्या-13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारोपरांत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया, का निर्णय लिया गया।

नियोजन विभाग ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की है कि नियोजन की दृष्टि से सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर को सुरभि पब्लिक स्कूल के लिए आवंटन पर नियोजन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उचित होगा कि पूर्व में उक्त स्कूल को आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर को सुविधाओं हेतु आरक्षित कर दिया जाये। इस संबंध में आवंटन के नियम, शर्तें एवं दर तय करते समय इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 6331.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल भूखण्ड नियोजन माप-दण्डों के अनुसार कम है, अतः शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। उक्त आशय की अनुपालन आख्या दिनांक 15.07.2004 की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सम्यक विचारोपरांत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में पुनः प्रियदर्शिनी योजना के सेक्टर-बी में प्रस्तावित स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 3131.34 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को जन-सुविधाओं हेतु एवं जन-सुविधाओं हेतु अपेक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 6331.65 वर्ग मीटर के भू-उपयोग को प्राईमरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में पुनः विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

CTP
Chandra 14/3/04

Chandra

Chandra
26/11/2004

श्री राजा

उपस्थित अधिकारी

कृ. दूरभाष पर हुए बातों के क्रम से Circulate करावे।

18.11.04

बोर्ड बैठक दिनांक 17.05.2006 विषय संख्या 11 पर हुए निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या

बैठक में समिति ने कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी1 में एस0एस0-111 के ग्रीनबेल्ट में आवंटित भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। यह पाया गया कि यह भूखण्ड वर्ष 1992 के आस-पास के वर्षों में आवंटित किये गये थे। इन भूखण्डों पर अधिकांशतः भवन निर्माण हो चुका है। अतः समिति यह उचित समझती है कि इन भूखण्डों के आवंटियों का कोई दोष नहीं है। जन-मानस प्रभावित न हो एवं हरित पट्टिका का भी क्षय न हो इसलिए हरित पट्टी 2.78 एकड़ का भू-प्रयोग हरित पट्टी से आवासीय में परिवर्तित करने तथा इतनी ही आवासीय क्षेत्र की भूमि सेक्टर-ओ अथवा ओ विस्तार में हरित पट्टी के रूप में छोड़ना उपयुक्त होगा। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि इस प्रकरण में लेआउट का अनुमोदन क्यों नहीं कराया जा सका के सम्बन्ध में तत्कालीन नियोजन विभाग एवं भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। तत्क्रम में अनुपालन आख्या बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत है।

(सी.पी. शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

(डी.आर. यादव)
मुख्य अभियन्ता

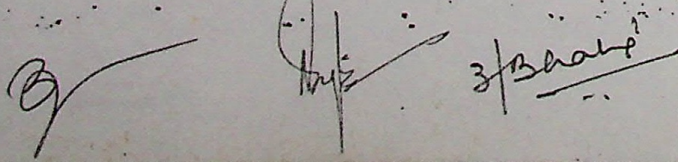
(डा. राम विलास यादव)
सचिव

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि
आवंटन के सम्बन्ध में।

अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डा० नरेन्द्र सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.2006 के माध्यम से अपनी संस्था इन्टर नेशनल सोसाइटी फार हरबल मेडिसिन्स, की स्थापना हेतु 6-7 एकड़ भूमि के आवंटन किये जाने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने कार्यालय पत्र संख्या 509/बल्क सेल दिनांक 24.08.06 द्वारा हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-आई में 31731 (7.8 एकड़) संस्थागत भूमि को ₹0 4,500.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया था। संस्था द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 29.08.06 द्वारा यह अनुरोध किया है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि समिति जिसके तत्वाधान में यह अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान चल रहा है सुयोग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों से तो सम्पूर्ण रूप से सम्बद्ध है किन्तु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अतः रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाए।

संस्था के चैरीटेबल होने के सम्बन्ध में आयकर विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है तथा संस्था सोसाइटी एक्ट में वर्ष 1989 से पंजीकृत है। संस्था द्वारा कार्यकलापों एवं इसकी उपयोगिता के संबंध में विवरण भी संलग्न किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

1. समिति का प्रादुर्भाव वर्ष 1989 में उच्चीकृत फारमाकालोजी एवं थैराप्यूटिक्स विभाग KGMC लखनऊ में हुआ।
2. समिति का उद्देश्य ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी व अन्य लोक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को विश्व के मध्य प्राचीनतम विद्या "वन औषधियों द्वारा चिकित्सा" के ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना है।
3. समिति अब तक दो राष्ट्रीय स्तर की व दो विश्व स्तर की वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ विभिन्न संस्थान एवं केन्द्रीय स्व०प०क० मंत्रालय के साथ मिलकर वर्ष 1993, 1995, 2003 व 2004 में बायोटेक्निकल डबलपमेन्ट्स इन हर्बल मैडिसिन व सम्बन्धित विषयों पर आयोजित कर चुकी है।
4. समिति अपने सदस्यों एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का सहयोग प्राप्त करके समय समय पर कई प्रकार के स्वास्थ्य रक्षा चिकित्सा शिविर जागरूकता के लिये प्रदेश में

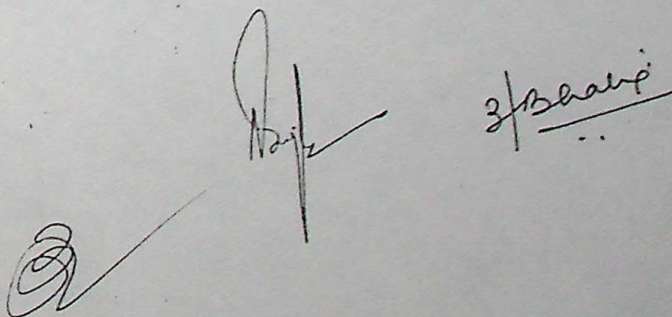


विभिन्न स्थानों पर आयोजित करके जनता की निःशुल्क परामर्श चिकित्सा एवं औषधि वितरण करती रही है।

5. समिति ने अब तक देश व विदेशों के नामी गिरामी वैज्ञानिकों चिकित्सकों एवं दवाई बनाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को अपनी fellowship award कर सम्मानित भी किया है।
6. समिति के अध्यक्ष डा० नरेन्द्र सिंह, एम०डी० को अब तक चौधरी चरण सिंह अवार्ड, डा० मुखर्जी अवार्ड व कई अन्य अवार्डों से पुरस्कृत किया जा चुका है।
7. संस्थान, समाज में रूग्ण व्यक्ति जो विभिन्न असाध्य व्याधियों से ग्रसित है हेतु न केवल अपने शहर लखनऊ एवं समस्त उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत एवं विदेशों में भी अपनी चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श एवं औषधियां निःशुल्क प्रदान कर, अब तक लगभग दो लाख रोगियों का उपचार कर लाभ पहुंचा चुका है।
8. संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि :-
 - 1 एक चिकित्सालय भी प्रारम्भिक चिकित्सा के लिये स्थापित किया जायेगा।
 - 2 लुप्त प्रायः वन औषधियों की प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जायेगा।
 - 3 प्रस्तावित नये स्वरूप में संस्थान को Deemed University का स्वरूप दिया जा सकेगा जहाँ वन औषधियाँ व इनसे सम्यक रूप से की जाने वाली चिकित्सा की पढाई भी प्रारम्भ की जा सकेगी।

महायोजना के प्राविधानों के अन्तर्गत हरदोई रोड योजना में सेक्टर-आई-1 में प्रस्तावित भूमि का भू-प्रयोग संस्थागत है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न दातव्य संस्थाओं के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए भूमि को रियायती दर (आवासीय दर की 50 प्रतिशत) पर आवंटन किया गया है।

अतः संस्था के उपरोक्त विवरण एवं उद्देश्यों तथा उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान (इन्टर नेशनल सोसाइटी फार हरबल मेडिसिन्स) को हरदोई रोड योजना के सेक्टर-आई-1 के संस्थागत क्षेत्र में यथोचित भूमि का आवंटन आवासीय दर की 50 प्रतिशत पर किये जाने के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



सेवा में,

दिनांक : 29/8/06

माननीय उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान 2/301, विजय खण्ड, गोमतीनगर को हरदोई रोड योजना में आवंटित भूमि न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके पत्र सं. 509/ बल्कसेल दि. 24.08.2006 के सन्दर्भ में सर्वप्रथम तो हम आपको प्रभावी एवं कृपणीय कृत्य के लिये धन्यवाद देते हुये आपकी मानव मात्र के उत्थान के प्रति समर्थित भावनाओं एवं हृदय की विशालता के लिये हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं जिसे कृपया स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें।

माननीय जैसा कि कई बार वार्तालापों के बीच आपके संज्ञान में लाने का प्रयास भी किया है, पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि समिति जिसके तत्वाधान में यह अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान चल रहा है सुयोग्य एवं अनुभवी वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों से तो सम्पूर्ण रूप से समृद्ध है किन्तु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

इसके उपरान्त भी यह संस्थान समाज में रूग्ण व्यक्ति जो विभिन्न असाध्य व्याधियों से ग्रसित हैं न केवल अपने शहर लखनऊ एवं समस्त उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत एवं विदेशों में भी अपनी चिकित्सा सुविधायें, परामर्श एवं औषधिया निःशुल्क प्रदान कर, अब तक लगभग दो लाख रोगियों का उपचार कर लाभ पहुंचा चुका है। इसके अतिरिक्त समय समय पर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वस्तर पर वर्ष 1993, 1995, 2003, 2004, 2005 में वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कर इस चिकित्सा पद्धति का न केवल प्रचार प्रसार ही किया अपितु इसने सम्भावित लाभ रोगियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कृषकों इत्यादि का भरपूर

सहयोग प्राप्त किया हैं। हमने अपनी वैदिक एवं आयुर्वेदिक पद्धतियों को सम्मानित रूप देकर विश्व आन्दोलन के रूप में उभारा है, और भारत वर्ष ने एक बार फिर से विश्व के सबसे पुराने मानव विज्ञान को जागरुकता दी है।

जैसा कि आजकल विकसित देशों में आहार विहार भोजनोपयोगी प्राकृतिक वस्तुओं तथा सौन्दर्य प्रसाधनों में हैवी मेटलस एवं उन्नत कृषि के तकनीकों के फलस्वरूप कृषि उपज के प्रयोग से पैस्टीसाइड रैजिड्यू के कुप्रभावों से मानव मात्र को अपूर्तिय क्षति के साथ ही प्रकृतिक स्वास्थ्य के लिए भी गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी हैं।

आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी व अन्य दवा बनाने वाली कम्पनियों द्वारा हमारे प्राकृतिक श्रोतों का इतनी तीव्रता से दोहन किया गया है कि कई प्राण रक्षक दवाईयों के पौधे जो प्राकृतिक वातावरण में ही पनप पाते हैं उनकी प्रजातियां प्रायः लुप्त ही हो रही हैं। यदि संभल रहे हैं इनका संरक्षण एवं संवर्धन नहीं किया गया तो अपना प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण देश भी अपनी प्रकृतिक सम्पदा से विहीन हो जायेगा। इस प्रकार यह संस्था केवल विलुप्त वन औषधियों का केवल संरक्षण ही नहीं करेगा बल्कि हर्बल पद्धति जो चार दशकों में वैज्ञानिक रूप से विकसित की गई है मनुष्य का प्रभावी उपचार करेगा। ये आधुनिक वैज्ञानिक औषधियों के साथ मिल कर एवं आधुनिक निदानिय तकनीकों का प्रयोग करते हुये असाध्य रोगों की साध्य चिकित्सा करेंगे। यह अपने में जीवित एवं जैविक प्रणाली का वैदिक विधानों के द्वारा उपचार का प्रथम संस्थान होगा, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अपनी समीक्षाओं में संस्तुति की है।

इस सम्पदा का तथा आयुर्वेद अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक पुष्टि प्रदान करने के लिये हमारी संस्था अभी तक प्रथम एवं आखिरी संस्था है और यह करने का उपयुक्त ज्ञान किसी भी वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक संस्थानों को नहीं है। यह हमारे स्वयं के प्रयत्नों द्वारा 40 वर्षों का अनुसंधान एवं अनुभव है। भारत में आज बहुत से अनुसंधान संस्थान हैं लेकिन उनके अनुसंधान मनुष्य मात्र की व्याधि एवं स्वास्थ्य के लिये आज तक सफल नहीं हो सके हैं।

उपरोक्त चिकित्सा पद्धति हानि रहित एवं जीवन दायनी है इसका पुष्टिकरण सारी दुनिया में केवल हमारा ही संस्थान एक मात्र कर सका है। हम विश्व भर के वैज्ञानिकों को जो हर्बल औषधियों में ज्ञाता हैं कई बार एकत्रित कर चुके हैं और सभी को संस्थान के कार्य कलापों का पता है। हमने इन संगोष्ठियों में थोड़ा थोड़ा आर्थिक अनुदान प्राप्त करके इनका

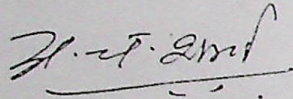
सफल आयोजन करके संसार में इस पद्धिती को ख्याति तो दिलवा दी हैं किन्तु जो कुछ आर्थिक अनुदान मिला वो उररी समय उपयोग में ले लिया गया हैं ।

अन्त में महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में इस प्रकार का कार्य करने वाली एक मात्र यह ही ऐसी संस्था हैं जो मानव मात्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं । और यदि सम्भव हुआ तो आपके द्वारा आंवरित भूखण्ड पर निर्मित होने वाले संस्थान को एक वृहत विश्वविधालय का स्वरूप भी भविष्य में जल्दी ही दिया जा सकेगा । इससे जो ज्ञान हम लोगों ने अपने अथक प्रयासों से लगभग चार दशकों में अनुभव किया हैं वह आने वाली सन्तति में भी ज्ञानोपार्जन के लिये वितरित किया जा सकेगा ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना हैं कि उपयुक्त कार्य कलापों का सज्ञान लेते हुये जो भी सम्भव हो इस भूखण्ड को न्यूनतम दर पर आवंटित करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

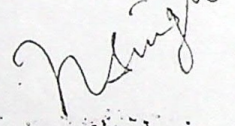
भवदीय



(डा० सतीश चन्द्र शर्मा)

महासचिव

भवदीय



(डा० नरेन्द्र सिंह)

निदेशक

अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान

2/301, विजय खण्ड, गोमतीनगर

लखनऊ

संख्या 2908

21/7/04



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 635, 2004,

फाइल संख्या I = 97608,

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इंटर नेशनल सोसाइटी फार -

हरकल मेडिसिनल लैबरनरी /

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 5508/88-89,

दिनांक 02-02-1989 को दिनांक 02-2-2004, से पांच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

340 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 20-7-2004,

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
हरकल प्रदेश।

गोपनीयता सूचना - एनपीआर 6 फॉर्म नियमांक-18.2002-(419)-50,000 प्रतिमा (कंप्यूटर/आफसेट)।

सिधामो, सिद्धोद्गी,

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त-1,
लखनऊ ।

इण्टरनेशनल सोसायटी फ़ार हरबल मेडिसिन्स, 2/301 विजय खण्ड-11, गोमती नगर, लखनऊ जो कि संस्थान / न्यास के ज्ञापन दिनांक 02.02.1989 द्वारा बनाया गया है, के पंजीकरण का प्रार्थनापत्र आयकर अधिनियम की धारा 12A(a) के अधीन विहित प्रारूप में दिनांक 15.07.2005 को दिया है, जो कि निर्धारित अवधि में समय से नहीं है।

2. मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे दिनांक: 01.04.2005 से इस कार्यालय में प्रयुक्त 12A(a) के रजिस्टर में क्रम संख्या 46 / 06 / 2005-06 पर पंजीकृत किया जाता है।

Copy filed

(Vivek Narayan)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त-1
लखनऊ

(विवेक नागरथ)

आयकर अधिकारी, (मु.) तकनीकी
कृते आयकर आयुक्त-1, लखनऊ।

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त-1,
लखनऊ ।

के० सं० 58-59/35 /05/2005-06/ तक./आ. आ.-1/लख/
प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक : 25.01.2006

१ उपर्युक्त आवेदक को सूचनार्थ

२ 12A सहायक आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी 2(2) रेंज--11, लखनऊ ।

४ 12A अपर आयकर आयुक्त / रेंज -11, लखनऊ ।

(विवेक नागरथ)

आयकर अधिकारी, (मु.) तकनीकी
कृते आयकर आयुक्त-1, लखनऊ ।

To,

Dated: 17.06.2006

Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Lucknow.

Sub: Gift of land (6 to 7 acres) for International Institute of Herbal Medicine (IIHM), Lucknow.

Dear Sir,

This is to invite your kind attention to the following facts that the International Institute of Herbal Medicine (IIHM), a body of the International Society for Herbal Medicines (ISHM, registered under Society Act 1860) is also associated closely with the "Association for Modernized Promotion of Asian Traditional Medicines" (AMPATM) consisting of twelve Asian countries.

The Society (ISHM) was established in 1988 and the Institute (IIHM) in 1995 since then two World conferences and two National conferences were held by the Society, Biotechnological Development of Herbal Medicines in 1993, World Congress 1995, 2nd World Congress 2003 & National conference in 2004. These conferences have brought together scientist of various fields working with Herbals and Ayurveda. This did not only include prominent Scientist from India but also top Biomedical Scientist from the world such as Memory E Lewis, Walter H Lewis – Head of the department of Biomedicine, Washington University, Dr. Ralph Miller – Ex. Director of Health Services, Canada etc. they all have been honoured with the fellowship of the Society (ISHM) and are collaborating continuously with the Institute's ongoing research programmes and visiting the Institutes at regular intervals.

Somehow, due to lack of obtainable funds, the Institute (IIHM), which is No. 1 in the country for Herbal Medical Research and Substantiation Scientifically of Indian Herbs of Ayurveda for their use all over the world. Even having an International Reputation Scientifically remained without its own building and required infrastructure.

Your timely help by providing us with 6-7 acres of land on suitable location will provide space for building prestigious Institute with all modern equipments and facilities. Top Scientist, many of whom reside in Lucknow itself are available to work and research for the institute. The area is required because the Institute will have the Laboratories, small Hospital, Quarters for Scientists and Workers, thus will bring the name of Lucknow on the International map as the core centre of Herbal Research for the whole world. People from all strata of the society from Lucknow will be employed for different functions of the Institute. Training of the Scientist in this field will be done for the first time in India and the world in this Institute. This will bring our ancient culture of medicinal herbs on top and we will not be second to any country like China, which provides herbal medicine to the whole world.

The aim of the Institute is to provide scientific data for standard medicinal herbs, their usefulness with high reliability and quality, which is missing in the ancient system of Indian medicines. I wish to emphasize that during the last ten years the use of plant medicines/traditional formulations has become a topic of increasing global importance with both medical and economic implications. Today 70% or may be even more than that of the public world over believe that the herbal medicines/formulations as well as cosmetics are safe and effective. Such widespread use of these medicines and cosmetics raises the questions regarding quality, safety and efficacy of their products. It is essential, therefore, that we should have highly trained professionals with expertise in the fields of Pharmacognosy, Pharmacology, Biochemistry, Microbiology, Toxicology, Analytical, Pharmaceutical Chemistry & allied subjects who can validate the herbal traditional formulations/medicines as well as cosmetological products.

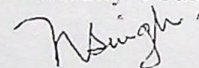
That in order to fulfil the above needs there is an urgent need to establish a centre of relevance and excellence for validation of products marketed by various pharmaceuticals and cosmetics companies for saving the general public from their possible hazards, making them aware not to be carried away in the name of misconception about safety and effectiveness of herbals. This will be revival of cultural heritage and honours of our country in this field.

Hope to get a favourable response from you.

Encls:

1. Copy of Registration of the Society
2. Copy of Memorandum indicating aims and Objects
3. Copy of the activities of the Society
4. Copies of cover pages of Souvenirs
of the Seminars and conferences held
5. Tulsi Book cover page
6. Biodata of Dr. N. Singh, Director IIHM
& President ISHM

Gratefully Yours



(Dr. Narendra Singh)
President

International Institute of Herbal Medicine
&

Director
International Society for Herbal Medicine

2/301, Vijaykhand - II
Gomtinagar

Lucknow - 226010

119

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 04 सितम्बर, 2006
में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1. | श्री राकेश कुमार मित्तल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री बी०बी०सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ। |
| 3. | श्री रमेन्द्र त्रिपाठी | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 4. | श्री राम बोध मौर्या | नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम। |
| 5. | श्री ओम नारायण | निदेशक, कोषागार। |
| 6. | श्रीमती प्रभावती सिंह | संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग। |
| 7. | श्री पी.के.जैन | मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, |
| 8. | श्री ए.के.भटनागर | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि। |
| 09. | श्री सिजृन हटडे | मुख्य वास्तुविद, उ०प्र० आवास
एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 10. | श्री तुलसीराम चौरसिया | सदस्य, ल.वि.प्रा. |
| 11. | डा. फिदा हुसैन अंसारी | सदस्य, ल.वि.प्रा.। |

अन्य उपस्थिति:

12. श्री राम बिलास यादव सचिव, ल.वि.प्रा., लखनऊ ।
13. श्री सी०पी०शर्मा मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० ।
14. डा. मोहन यादव वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा. ।
15. श्री दवनराम यादव मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा० ।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय: प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 02 मई, 2006 के विषय संख्या : 10 (कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि निगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में) पर गठित उपसमिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार भूमि अर्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या : 3 बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में । (बोर्ड बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 में विषय संख्या: 28 के अन्तर्गत गठित समिति की आख्या)

②

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव एवं गठित समिति की संस्तुतियों के अवलोकनोपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 4 ग्राम हासेमऊ, भरवारा, लोनापुर, चन्दिमामऊ एवं बतकास में लखनऊ महायोजना 2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को आउटर रिंगरोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : मुख्य नगर नियोजक द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष बड़े मानचित्र की सहायता से प्रश्नगत स्थल को दर्शाते हुए महायोजना-2021 में प्रस्तावित सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करने एवं उक्त प्रयोजन हेतु आउटर रिंग रोड के पूर्व की ओर कृषि भू-उपयोग में सीवेज फार्म/सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उपाध्यक्ष द्वारा भी इसे परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। जन प्रतिनिधि श्री चौरसिया द्वारा अनुरोध किया गया कि नई योजनाओं में निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को भी दृष्टिगत रखते हुए योजनाये प्रस्तावित की जायें।
विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 5 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में विकसित डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में भूमि का आवन्टन।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा. राम मनोहर लोहिया पार्क के मध्य स्थित 132 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने तथा इस हेतु गोमती नगर विस्तार योजना में 220 के.वी.विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं देयता के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

①

- विषय संख्या : 6 गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में स्थित अवध अपार्टमेन्ट के दो नये 12 मजिले ब्लॉक्स का निर्माण कार्य।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय का मत था कि दो बेड रूम फ्लैट्स को भी सम्मिलित किया जाये।
- विषय संख्या : 7 एकल आवास तथा प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयों के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या : 8 हाईटेक टाउनशिप के लिये भूमि के चयन/अर्जन एवं डी. पी.आर. के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
- विषय संख्या : 9 मोतीझील योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : एसएस-281 तथा एसएस-282 के बगल में कल्डीसेक हेतु निर्धारित भूखण्ड को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : 10 खसरा संख्या: 221 स, निकट टी.वी.टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये।



विषय संख्या : 11 श्री राम कुमार शुक्ला वर्कचार्ज लिपिक को चिकित्सा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज लिपिक को रु0 50,000/-चिकित्सा सहायता के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 12 प्रदेश की प्रथम भू-जल संवर्धन एवं प्राचीन झील संरक्षण परियोजना (101 एकड़ में नगरीय वन की स्थापना) के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 13 ह्युमन ऐण्ड एजुकेशन रिसर्च सेन्टर, विपुल खण्ड-6, गोमती नगर स्थित तलपट मानचित्र में प्रायमरी स्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट/डिग्री कालेज किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन साधारण से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 14 प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना सेक्टर- बी, सीतापुर रोड में सुरभि पब्लिक स्कूल को आवन्तित 3131.34 वर्गमीटर भूमि को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रियदर्शनी योजना सेक्टर बी, सीतापुर रोड में आवन्तित 3131.34 वर्गमीटर के आवन्तित स्कूल भूखण्ड के स्थान पर 6331.65 वर्गमीटर का स्कूल भूखण्ड परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि बड़े हुए क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर तथा पूर्व में आवन्तित क्षेत्रफल हेतु पुरानी दर लगाई जायेगी।



विषय संख्या : 15 कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी-1 में एसएस-111 के ग्रीनबेल्ट में आवन्तित भूखण्डों के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या।

निर्णय : समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। भू-उपयोग परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।

विषय संख्या : 16 अन्तर्राष्ट्रीय वनौषधि अनुसंधान संस्थान को हरदोई रोड योजना में भूमि आवन्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि संस्था को अपने प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण (presentation) हेतु सूचित कर दिया जाये। यह प्रस्तुतिकरण अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय स्थित समिति कक्ष में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष किया जायेगा। इस प्रकरण पर विशेषज्ञ राय हेतु निदेशक, एन.बी.आर.आई. को भी आमन्त्रित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


(डा.राम बिलास यादव)
सचिव


(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(आर.के.मिस्तल)
13.9.06.

आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।